हिन्दी सान्ध्य दैनिक

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

वर्ष - 02 | अंक - 125 | जौनपुर, बुधवार 31 जनवरी 2024 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज - 4 | मूल्य - 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

लाल सागर में समुद्री डकैती के साथ ड्रोन हमलों की भी समस्या – जयशंकर

नई दिल्ली, एजेंसी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने व्यापारी नौसेना के जहाजों पर हमलों से निपटने के लिए लाल सागर क्षेत्र में भारतीय नौसेना द्वारा युद्धपोतों की तैनाती पर कहा कि भारत की अधिक क्षमता, उसका अपना हित और प्रतिष्ठा आज इस बात की गारंटी देती है कि वह वास्तव में कठिन परिस्थितियों में मदद करता है।

लाल सागर में भारतीय नौसेना के 10 जहाज तैनात

भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) मुंबई में छात्रों के साथ बातचीत के दौरान जयशंकर ने कहा कि भारतीय नौसेना ने इस क्षेत्र में अपने 10 जहाज तैनात किए हैं। भारत की अधिक क्षमता, हमारा अपना हित और हमारी प्रतिष्ठा आज इस बात की गारंटी देती है कि हम वास्तव में कठिन परिस्थितियों में मदद करें।

मर्चेंट नेवी जहाजों पर ड्रोन हमलों की भी समस्या

जयशंकर ने कहा कि लाल सागर क्षेत्र में समुद्री डकैती के साथ–साथ मर्चेंट नेवी जहाजों पर ड्रोन हमलों की भी समस्या है। अगर हमारे पड़ोस में बुरी चीजें हो रही हैं और हम कहते हैं कि मेरा इससे कोई लेना–देना नहीं है तो हमें जिम्मेदार देश नहीं माना जाएगा। जब आप परेशानी में होंगे तो पड़ोस भी यही कहेगा।

हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं के विकास के लिए किया एनजीईएल ने साथ समझौता

महाराष्ट्र, एजेंसी। महाराष्ट्र सरकार ने एनटीपीसी हरित एनर्जी लिमिटेड (एनजीईएल) द्वारा प्रति वर्ष एक मिलियन टन क्षमता तक हरित हाइड्रोजन और डेरिवेटिव (हरित अमोनिया, हरित मेथनॉल) के विकास के लिए एनजीईएल के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर सोमवार को हस्ताक्षर किए. इसमें 2 गीगावॉट के पंप स्टोरेज परियोजनाओं सहित राज्य में 5 गीगावॉट तक भंडारण के साथ अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं का विकास शामिल है। महाराष्ट्र सरकार की हरित निवेश योजना के एक भाग के रूप में अगले पांच वर्षों के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते में लगभग 80,000 करोड़ रुपए के संभावित निवेश की उम्मीद है। इस समझौता ज्ञापन का आदान–प्रदान 29 जनवरी, 2024 को महाराष्ट्र सरकार के उप सचिव (ऊर्जा) श्री नारायण कराड और एनजीईएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री मोहित भार्गव के बीच हुआ। एनजीईएल एनटीपीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और इसका लक्ष्य 7 गीगावॉट अक्षय ऊर्जा के परिचालन को शुरू करने के साथ 3.4 गीगावॉट और 26 गीगावॉट से अधिक की परिचालन क्षमता पर काम करते हुए एनटीपीसी की अक्षय ऊर्जा यात्रा का ध्वजवाहक बनना है।

फसलों के नुकसान का मुआवजा देने में लापरवाही पर सीएम योगी सख्त

लखनऊ, संवाददाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। क्षतिग्रस्त फसलों का मुआवजा देने में लापरवाही बरतने पर सीएम योगी ने नाराजगी जताते हुए 17 जिलों के अधिकारियों से जवाब तलब किया है। दरअसल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में विभिन्न आपदाओं से क्षतिग्रस्त हुई फसलों के मुआवजे और अन्य राहत को लेकर समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने त्रुटियों के कारण फसलों के नुकसान के दोबारा सत्यापन में लापरवाही और मुआवजा नहीं देने पर नाराजगी जताई और अधिकारियों को ऐसे मामलों में तत्काल सत्यापन कराकर किसानों को मुआवजा राशि प्रदान करने के स्पष्ट निर्देश दिये हैं। मालूम हो कि फसलों के नुकसान का सत्यापन करने के बाद प्रदेश सरकार की ओर से किसानों को मुआवजा राशि व अन्य राहत प्रदान की जाती है, लेकिन कुछ मामलों में तकनीकी कमियों के कारण कुछ किसानों की फसलों का सत्यापन पूर्ण नहीं हो सका। वहीं दोबारा उनका सत्यापन नहीं किया गया, जिससे कुछ किसान सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली राहत और मुआवजा राशि प्राप्त नहीं कर सके। इसी को लेकर सीएम योगी ने सख्ती जताते हुए अधिकारियों से जवाब तलब करने के साथ ही वंचित किसानों को तत्काल मुआवजा देने के निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक में पाया कि वित्तीय वर्ष 2021–22 और वर्ष 2022–23 में आपदाओं से क्षतिग्रस्त फसलों से प्रभावित हजारों किसानों को डाटा फिडिंग के दौरान आधार, खाता संख्या और डुप्लीकेसी के कारण मुआवजे का भुगतान नहीं किया जा सका जबकि उन्होंने अधिकारियों को दोबारा सत्यापन कराकर मुआवजे से वंचित किसानों को सहायता राशि देने के निर्देश दिये थे। सीएम योगी के निर्देश के बाद भी प्रदेश के कई जिलों के अधिकारियों ने क्षतिग्रस्त फसलों से प्रभावित किसानों का सर्वे नहीं कराया। इसकी वजह से समय से किसानों को मुआवजा नहीं मिल सका। इस पर उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कड़ी फटकार लगाई। इतना हीं नहीं उन्होंने लापरवाह 17 एडीएम एफआर से जवाब तलब करते हुए कड़ा एक्शन लेने के निर्देश दिये। सीएम योगी की नाराजगी के बाद हरकत में अधिकारियों ने अपने–अपने जिले में मुआवजे से वंचित किसानों का दोबारा सर्वे कराकर शासन से बजट की डिमांड की है। अपर मुख्य सचिव राजस्व सुधीर गर्ग ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न जिलों से क्षतिग्रस्त फसलों से प्रभावित वंचित किसानों को तत्काल मुआवजा देने के लिए डिमांड के अनुसार धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। अभी तक 35 करोड़ से अधिक की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है। साथ ही विभिन्न जिलों के जिलाधिकारियों को जल्द से जल्द मुआवजे से छुटे किसानों का सत्यापन कराकर धनराशि के डिमांड के निर्देश दिये गये हैं ताकि कोई भी किसान इससे वंचित न रह जाए। अपर मुख्य सचिव राजस्व ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 17 जिलों के एडीएम एफआर से लापरवाही पर जवाब तलब किया गया है। इनमें अलीगढ़, हाथरस, बाराबंकी, मऊ, बरेली, बदांयू, अंबेडकर नगर, शाहजहांपुर, महोबा, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, झांसी, ललितपुर, गाजियाबाद, बिजनौर और कौशांबी के एडीएम एफआर शामिल हैं। सभी एडीएम को एक हफ्ते में अपना जवाब शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने बताया कि सभी एडीएम से जवाब मिलते ही रिपोर्ट मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। सीएम योगी के निर्देश के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। राहत आयुक्त जीएस नवीन ने बताया कि बाढ़, ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश से 33 प्रतिशत से अधिक क्षतिग्रस्त फसलों से प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया जाता है। सीएम योगी के निर्देश पर किसानों को मुआवजा धनराशि सर्वे के 24 घंटे में डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में भेजी जा रही है।

जब तक जीवित हूं, बंगाल में सीएए लागू नहीं होने दूंगी – सीएम ममता

कोलकाता, एजेंसी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव से पहले सीएए का मुद्दा उठाने के लिए मंगलवार को भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि वह अपने जीवनकाल में राज्य में इसे लागू नहीं होने देंगी। उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज में सार्वजनिक वितरण कार्यक्रम के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने लाभ लेने के लिये आगामी चुनावों से पहले नागरिकता (संशोधन) अधिनियम यानी सीएए का मुद्दा उठाया है। चुनाव नजदीक आते देख, भाजपा ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए फिर से सीएए का मुद्दा उठाया है। मैं यह स्पष्ट कर दूं कि जब तक मैं जीवित हूं, पश्चिम बंगाल में इसे लागू नहीं होने दूंगी। बनर्जी ने केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता शांतनु ठाकुर के हालिया दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए यह बात कही है। पूरे देश में एक सप्ताह के अंदर सीएए लागू किया जाएगा। रविवार को दक्षिण 24 परगना जिले के काकद्वीप में एक जनसभा के दौरान दिए गए ठाकुर के बयान ने विवादास्पद कानून को लागू किए जाने को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में सीएए को मंजूरी दी थी। कानून में 31 दिसंबर 2014 से पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों सहित प्रताड़ित गैर–मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है।

यूजीसी के नए मसौदे से आरक्षण खत्म करने की साजिश - राहुल गांधी

नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की नई मसौदा गाइडलाइंस को उच्च शिक्षण संस्थानों में एससी, एसटी व ओबीसी वर्ग को दिए जाने वाले आरक्षण को खत्म करने की साजिश करार दिया है। पार्टी ने इस मामले में यूजीसी के चेयरमैन एम. जगदीश कुमार को बर्खास्त किए जाने की मांग की है। कांग्रेस ने रविवार को यूजीसी की इस नई मसौदा गाइडलाइंस को वापस लिए जाने की मांग की थी जिसमें यह प्रस्ताव किया गया है कि एससी, एसटी व ओबीसी के लिए आरक्षित किसी भी रिक्त पद को अनारक्षित घोषित किया जा सकता है अगर इन वर्गों से पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं। राहुल गांधी ने एक्स पर हिंदी में एक पोस्ट में कहा, 'यूजीसी के नए मसौदे में उच्च शिक्षण संस्थानों में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग को मिलने वाले आरक्षण को खत्म करने की साजिश हो रही है। आज 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में लगभग 7,000 आरक्षित पदों में से 3,000 रिक्त हैं और जिनमें सिर्फ 7.1 प्रतिशत दलित, 1.6 प्रतिशत आदिवासी और 4.5 प्रतिशत पिछड़े वर्ग के प्रोफेसर हैं। भाजपा– आरएसएस अब ऐसे उच्च शिक्षण संस्थानों में वंचित वर्ग के हिस्से की नौकरियां छीनना चाहते हैं। यह सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करने वाले नायकों के सपनों की हत्या और वंचित वर्गों की भागीदारी खत्म करने का प्रयास है। यही सांकेतिक राजनीति और वास्तविक न्याय के बीच का फर्क है और यही भाजपा का चरित्र है। 'कांग्रेस ये कभी नहीं होने देगी। हम सामाजिक न्याय के लिए लड़ते रहेंगे और इन रिक्त पदों पर भर्ती आरक्षित वर्गों के योग्य उम्मीदवारों से ही करवाएंगे। इस जनविरोधी कदम का कांग्रेस द्वारा विरोध के बाद यूजीसी को यह बयान जारी करने पर मजबूर होना पड़ा। कि ऐसा कोई भी फैसला नहीं किया गया है।

भारत की आत्मनिर्भरता अलगाव नहीं भाईचारा को बढ़ावा देता - राजनाथ

नई दिल्ली, एजेंसी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वैश्विक निवेशकों व खास तौर पर अमेरिका के कारोबारियों को यह आश्वस्त किया है कि उन्हें आत्मनिर्भर भारत की नीति से परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस नीति के जरिए ऐसा भारत बनाने की कोशिश नहीं है जो दुनिया से अलग हो कर रहे। रक्षा मंत्री ने यह बात मंगलवार को इंडो अमेरिकन चौंबर ऑफ कामर्स के एक कार्यक्रम में कही। रक्षा मंत्री से पहले इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नई दिल्ली में अमेरिका के राजदूत एरिक गार्सेटी ने भारत सरकार की मौजूदा कराधान संबंधी नीतियों के साथ ही आत्मनिर्भर भारत पर टिप्पणी की थी और कहा कि, "सब कुछ भारत में ही निर्माण करने को लेकर जरूरत से ज्यादा बयानबाजी का उल्टा असर भी हो सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि, मैं भारत की आत्मनिर्भरता को लेकर एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। हमारे आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य निरंकुशता नहीं है। हमारा उद्देश्य यह बिल्कुल भी नहीं है, कि हम वैश्विक व्यवस्था से ही कट जाए। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत हम ऐसा भारत बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहते, जो दुनिया से अलग रहकर काम करे। हमारा आत्मनिर्भर भारत का कार्यक्रम आपसी साझेदारी को बढ़ावा देता है। हमारी तो संस्कृति ही श्वसुधैव कुटुंबकमश्श की है, जब हमारे लिए पूरी दुनिया ही एक परिवार है, तो हम दुनिया से अलग रहकर भला अपना विकास कैसे कर सकते हैं। "भारत में कारपोरेट टैक्स से जुड़े नियम काफी अस्पष्ट हैं और इन्होंने अमेरिकी कंपनियों के निवेश संबंधी फैसले की राह में अड़चनें पैदा की हैं। वो भारत में निवेश करना चाहती हैं लेकिन अपनी बौद्धिक संपदा का संरक्षण चाहती हैं। सीमा शुल्क, नियमन व टैक्स संबंधी नियमन हमेशा आर्थिक समृद्धि को बढ़ाते हैं।

बीजेपी के पास बेरोजगारी का समाधान नहीं, मोदी की गारंटी एक जुमला है –प्रियंका गांधी

नयी दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पास देश के सबसे बड़े मुद्दे बेरोजगारी का कोई समाधान नहीं है और 'मोदी की गारंटी' जैसी बातें ''सिर्फ जुमला'' हैं। वाद्रा ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक वीडियो भी साझा किया जिसमें बड़ी संख्या में लोग इजराइल में नौकरी पाने के मकसद से कतारबद्ध नजर आ रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा, अगर कहीं पर युद्ध के हालात हैं तो सबसे पहले हम अपने नागरिकों को वहां से बचाकर, वापस अपने वतन लाते हैं लेकिन बेरोजगारी ने आज ये हाल कर दिया है कि देश की सरकार हजारों असहाय और मजबूर युवाओं को युद्धग्रस्त इजराइल जाकर ये खतरा उठाने से भी बचा नहीं रही। इसी से पता चलता है कि चुनावों में '5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था, सालाना दो करोड़ रोजगार और मोदी की गारंटी जैसी बातें ''सिर्फ जुमला'' हैं। कांग्रेस महासचिव ने कहा, यहां, अपने देश में इन्हें रोजगार क्यों नहीं मिल रहा? लंबी–लंबी कतारों में दो–दो दिनों से खड़े युवा क्या हमारे देश के बच्चे नहीं हैं कि हम इन्हें खुशी से इतने भयानक युद्ध के बीच भेजने को तैयार हैं? कितनी चालाकी से सरकार इसे देश के युवाओं का व्यक्तिगत मसला बना रही है।

जेपी नड्डा से मिले मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव

नई दिल्ली, एजेंसी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर उन्हें प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे कामकाज की जानकारी दी। जेपी नड्डा के आवास पर हुई बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा की। दिल्ली दौरे पर आए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इससे पहले केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन एवं श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव से उनके निवास पर और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी तथा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन स्थित उनके कार्यालय में भेंट कर राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। विभिन्न लंबित प्रकरणों पर शीघ्र निराकरण करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि प्रदेश में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की केंद्रीय योजनाओं को मूर्त रूप देने में मध्य प्रदेश शासन सदैव प्रयासरत है और प्रदेश में केंद्र और राज्य शासन की अनेक योजनाएं सफलतापूर्वक संचालित की जा रही हैं।मध्य प्रदेश शासन से केंद्रीय मंत्रालय को भेजे गए कुछ प्रस्ताव काफी समय से लंबित हैं, जिनका त्वरित निराकरण किया जाना प्रदेशहित में होगा। उन्होंने राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड की स्टैंडिंग कमेटी के समक्ष तथा वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रदेश के लंबित प्रकरणों की ओर भी केंद्रीय मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

मोदी सरकार ने 10 साल में बहुत कुछ किया - अमित शाह

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार मई में अपने 10 साल पूरे करने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि इस सरकार ने मजबूत ग्रामीण विकास की नींव रखी है। शाह का यह बयान राष्ट्रीय राजधानी में कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज की कम्प्यूटरीकरण परियोजना शुरू करने के बाद आया है। यह कार्यक्रम सहकारिता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के सहयोग से आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार मई में अपने 10 साल पूरे करने वाली है। उन्होंने कहा, पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने दो बड़े काम किए हैं– एक देश के 23 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालना और 60 करोड़ गरीबों को बिजली के साथ–साथ मुफ्त राशन जैसी सुविधाएं मुहैया कराना और दूसरा स्व–रोजगार लाने के लिए सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की। उन्होंने कहा, भाजपा की मोदी सरकार ने मजबूत ग्रामीण विकास की नींव रखी है। शाह ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के एआरडीबी और आरसीएस कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण प्रधानमंत्री मोदी के सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में सहयोग मंत्रालय द्वारा उठाए गए कई महत्वपूर्ण कदमों में से एक है। एआरडीबी की कंप्यूटरीकरण परियोजना का लक्ष्य 13 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में स्थित एआरडीबी की 1,851 इकाइयों को कंप्यूटरीकृत करना और उन्हें एक सामान्य राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर के माध्यम से नाबार्ड से जोड़ना है। उन्होंने कहा, सहकारिता मंत्रालय की इस पहल से कॉमन अकाउंटिंग सिस्टम और प्रबंधन सूचना प्रणाली के माध्यम से व्यावसायिक प्रक्रियाओं को मानकीकृत करके एआरडीबी में परिचालन दक्षता, जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ेगी। कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण के लिए लगभग 225 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

संपादकीय

चुनावी उदासी

पाकिस्तान में एक सप्ताह से कुछ अधिक समय बाद चुनाव होने जा रहे हैं। फिर भी उतना उत्साह नहीं है जितना आम तौर पर तब होता है जब चुनाव करीब होते हैं। हमने उम्मीदवारों द्वारा सामान्य रूप से रंगीन चुनाव अभियान नहीं देखा है या पर्याप्त राजनीतिक रैलियां नहीं देखी हैं जैसा कि हम अन्य अवसरों पर देखते हैं। यहां तक कि जो रैलियां हो रही हैं, वे भी थोड़ी मजबूर लग रही हैं. ऐसा शायद चुनावों से जुड़ी अनिश्चितता के कारण हो सकता हैरू कोई नहीं जानता कि चुनाव समय पर होंगे या नहीं या कौन जीतेगा और अंततः अगली सरकार बनाएगा। विश्लेषकों का कहना है कि हालांकि यह लगभग तय है कि चुनाव 8 फरवरी को होंगे, लेकिन अगली सरकार के गठन को लेकर अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल अपने दम पर ऐसा करने के लिए पर्याप्त सीटें हासिल नहीं कर पाएगा। हम संभवतः एक बार फिर गठबंधन सरकार देखेंगे। विश्लेषकों का यह भी कहना है कि चुनाव को लेकर उत्साह की कमी इसलिए हो सकती है क्योंकि कई मतदाताओं का मानना है कि अंत में उनके वोट कोई मायने नहीं रखेंगे क्योंकि शक्तिशाली तबकों ने पहले ही फैसला कर लिया है कि एक राजनीतिक दल 'अस्वीकार्य' है और उसे 'गठन की अनुमति' नहीं दी जाएगी। सरकार। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो–जरदारी पिछले कुछ समय से चुनावी रैलियां कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) के नेता नवाज शरीफ ने जनवरी के मध्य के बाद ही अपना अभियान शुरू किया था। इमरान खान जेल में बंद हैं. उनकी पार्टी, पाकिस्तान तहरीक–ए–इंसाफ, खस्ताहाल में हैरू इसके कई नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है और उनमें से कई छुपे हुए हैं। पीटीआई के लिए सबसे बड़े झटके में से एक इस महीने सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि जिस तरह से पीटीआई के इंट्रा–पार्टी चुनाव हुए थे दृ या बिल्कुल नहीं हुए थे, उसके कारण उसका चुनाव चिह्न, 'बल्ला' नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के विस्तृत फैसले में कहा गया, "किसी भी राजनीतिक दल को किसी भी सामान्य उल्लंघन के लिए चुनाव चिन्ह से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। हालाँकि, अंतर–पार्टी चुनाव न कराना संविधान और कानून का सबसे बड़ा उल्लंघन है। कई कानूनी विशेषज्ञों की राय है कि यह न्याय का मखौल है और पीटीआई को आम चुनाव से कुछ हफ्ते पहले उसका चुनाव चिन्ह नहीं छीनना चाहिए था क्योंकि यह राजनीतिक भागीदारी के संबंध में मौलिक अधिकार न्यायशास्त्र का उल्लंघन करता है। फैसले के कारण, पीटीआई के उम्मीदवार अब अलग–अलग चुनाव चिन्हों के साथ 'निर्दलीय' के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। जबकि पीटीआई ने यह सुनिश्चित करने के लिए सोशल मीडिया अभियानों और प्रौद्योगिकी का उपयोग किया है कि उसके मतदाताओं को पता चले कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में उसका आधिकारिक उम्मीदवार कौन है और उसका चुनाव चिन्ह क्या है, विश्लेषकों का कहना है कि मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा 'आधिकारिक' के बारे में भ्रमित है। पार्टी के उम्मीदवार और उनके प्रतीक। ऐसा इसलिए है क्योंकि कई निर्वाचन क्षेत्रों में, कई आशावानों ने पार्टी टिकट के लिए आवेदन किया है। अगर पार्टी को 'बल्ला' आवंटित किया गया होता, तो पीटीआई मतदाताओं के लिए कोई भ्रम नहीं होता। लेकिन कई लोग अब आधिकारिक पार्टी उम्मीदवारों से अनजान हैं। विश्लेषकों का कहना है कि यह पीटीआई की सबसे कम चिंता हैरू पार्टी के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि चूंकि उसके लगभग 234 उम्मीदवार अब निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए पार्टी अनुशासन उन पर लागू नहीं होता है। एक बार जब वे जीत जाते हैं, तो वे पीटीआई वोट के कारण जीतने के बावजूद चुनाव के बाद अन्य राजनीतिक दलों में शामिल हो सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 63–ए के तहत दलबदल खंड स्वतंत्र उम्मीदवारों पर लागू नहीं होता है। कई पार्टियां अब इन निर्दलियों को अपने लिए फायदेमंद मान रही हैं। यही कारण है कि कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह निर्दलियों का चुनाव है क्योंकि यदि कोई भी राजनीतिक दल अगली सरकार बनाने के लिए पर्याप्त सीटें या साधारण बहुमत हासिल नहीं कर पाता है तो वे ही निर्णायक भूमिका निभाएंगे। लोकतांत्रिक देशों में चुनाव संघर्ष–समाधान का एक साधन है। लेकिन पाकिस्तान में अपेक्षाकृत स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के नतीजे भी कुछ लोगों को स्वीकार्य नहीं हैं। कई लोगों को उम्मीद है कि ये चुनाव, भले ही विवादास्पद हों, कुछ स्थिरता लाएंगे। उनका तर्क है कि चुनाव खत्म होने के बाद देश को ठीक करने के लिए एक मंच के रूप में संसद का उपयोग किया जाना चाहिए। सभी राजनीतिक दलों को एक साथ बैठकर पाकिस्तान के लिए आगे का रास्ता तैयार करने की जरूरत है ताकि आज जो ध्रुवीकरण हम देख रहे हैं वह हमेशा के लिए खत्म हो जाए।

वर्तमान परिवेश में गांधी दर्शन की प्रासंगिकता - आचार्य (डा0) विक्रम देव

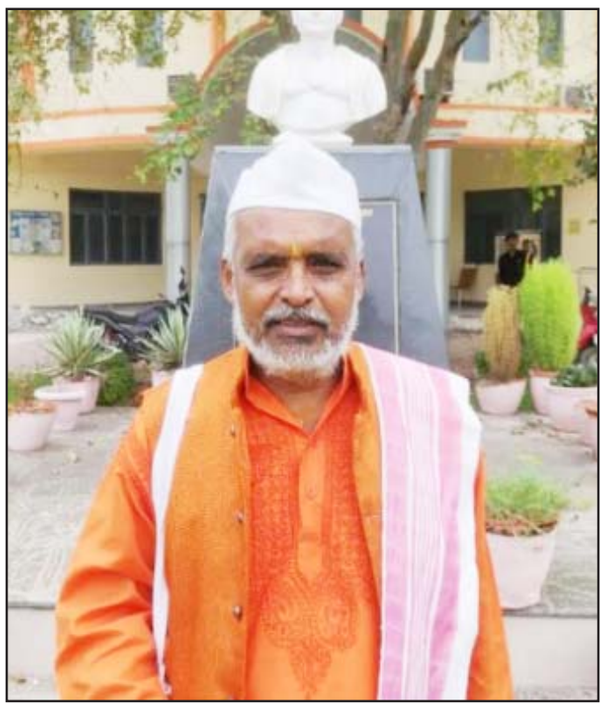

राम राज्य एवं अखण्ड भारत के सबसे बड़े पैरोकार वैष्णव संत राम भक्त गांधी महात्मा वैश्विक महामानव हैं। वे अपने उदात्त विचारों सर्वोदय, ग्रामोदय, अंत्योदय और सत्याग्रह से सदा अमर रहेंगे! उन्हे विश्व के लोग सदा सर्वदा याद करेंगे! गांधी दर्शन का यह प्रबल सिद्धांत है कि सत्य, अहिंसा और न्याय का आधार आध्यात्मिक ज्ञान और प्रेरणा है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य सांसारिकता से मुक्ति पाकर आध्यात्मिक सुख को प्राप्त करना है। इसी उद्देश्य को दृष्टिगत रखकर गांधी विचारधारा समाज की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का संतुलित रूप तैयार करना चाहती है। बापू की उपाधि गांधी महात्मा को 6 जुलाई 1944 को महान क्रांतिवीर नेता जी सुभाष चंद्र बोस ने प्रदान की थी। यह उपाधि गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी ष्बा ष के निधन पर शोक स्वरूप सिंगापुर रेडियो के माध्यम से उनके संबोधन पर दिया गया था। बापू शब्द का अर्थ षपिता ष है। उनको ष्महात्मा ष और ष्राष्ट्रपिता ष के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें महात्मा की उपाधि गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर ने एवं ष्राष्ट्रपिता ष की उपाधि खुद नेता जी ने प्रदान की थी। अहिंसा गांधीवादी विचारधारा का आधार थी, इसलिए यह स्पष्ट था कि राजनीति की जड़ें भी इसी में थीं । आवश्यकता थी । नई राजनीति से यह धारणा की गई कि वह अपने लोगों के मध्य शक्ति की भावना व साहस का निर्माण करेगी। यह भी आशा की गई कि शक्तिशाली स्थानीय समुदायों को समृद्ध करके नई राजनीति भारतीय समाज की विविधता का आदर करेगी। गांधी दर्शन का यह प्रबल सिद्धांत है कि सत्य, अहिंसा और न्याय का आधार आध्यात्मिक ज्ञान और प्रेरणा है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य सांसारिकता से मुक्ति पाकर आध्यात्मिक सुख को प्राप्त करना है। इसी उद्देश्य को दृष्टिगत रखकर गांधीवादी विचारधारा समाज की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का संतुलित रूप तैयार करना चाहती है। किसी भी शोषण का अहिंसक प्रतिरोध, सबसे पहले दूसरों की सेवा, संचय से पहले त्याग, झूठ के स्थान पर सच, अपने बजाय देश और समाज की चिंता करना आदि विचारों को समग्र रूप से गांधीवाद की संज्ञा दी जाती है। गांधीवादी विचार व्यापक रूप से प्राचीन भारतीय दर्शन से प्रेरित है और इन विचारों की प्रासंगिकता अभी भी बरकरार है। गांधी–दर्शन के चार आधारभूत सिद्धांत हैं– सत्य, अहिंसा, प्रेम और सद्भाव। वह बचपन में ष्सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ष नाटक देखकर सत्यावलंबी बने। उनका विश्वास था कि सत्य ही परमेश्वर है। उन्होंने सत्य की आराधना को भक्ति माना और अपनी आत्मकथा का नाम ष्सत्य के प्रयोग ष रखा । वे कठिन एवं संकट के समय में उपवास पर रहकर देश भर में शांति और सद्भाव स्थापना के लिए आजीवन कार्य करते रहे. कथित स्वतंत्रता के 6 माह बाद भी वे शारीरिक रूप से उपस्थित न रहे. उनकी हत्या 30 जनवरी,1948 को दिल्ली के बिरला मंदिर में कर दी गई जबकि वे 2 दिन बाद 1 फरवरी से आजादी बचाओ नाम से एक बड़ा आंदोलन प्रारंभ करने वाले थे। लेकिन सत्ता के दलाल उन्हे अपने रास्ते का कांटा समझकर विदा कर दिए। इस कारण यह देश , यहां का जनतंत्र , सत्ता की मशीनरी भी गांधी जी के विचारों के अनुरूप न बन सकी. फिर भी , लंबे समय तक आर्थिक नीतियों पर उनकी छाप निर्धनों, कमजोर वर्गों , स्त्रियों के लिए संजीवनी की भूमिका निभाती रही। वर्ष १९२० ६ १९३० से अफ्रीका से प्रारंभ उनका संघर्ष एक शताब्दी पश्चात भी विश्व में अहिंसा , शांति , सामाजिक सद्भाव और सर्व धर्म सद्भाव के मूल्यों को लेकर कार्य करने वालों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। गांधी महात्मा जी के विचारों की प्रासंगिकता सर्वकालिक और सर्वव्यापी इसलिए है कि, समाज में अन्याय , स्वार्थ , विषमता ,शोषण अभी भी विद्यमान है. इन प्रवृत्तियों में परिवार , समूहों , समाज ,देश और विश्व में वृद्धि होती जा रही है. मानवीय मूल्यों में विश्वास करने वालों के लिए बापू जी के विचार आदर्श के रूप में हैं. जिनका पालन वह जारी रखे हुए हैं. बापू जी जीवन मूल्यों पर आधारित गांधी दर्शन पर यूरोप एवं अमेरिका सहित समूचे विश्व के शिक्षा संस्थानों में पाठ्यक्रम चलाए जा रहे। उनके स्वदेशी एवं स्वालंबन के दर्शन को अपना कर बहुत सारे देश विकसित एवं संपन्न , समृद्ध राष्ट्र बन गए। अन्य दार्शनिक , धार्मिक ,आध्यात्मिक विचारों के समान गांधी के विचारों में विश्वास करने वालों को कोई शीघ्रता नहीं है , उनके प्रयत्न अवश्य जारी हैं क्योंकि ,यह संघर्ष न सत्ता का हे, न पूंजी और वैभव का और न विलासिता पूर्ण जीवन का गांधीवादी समाजवाद मुख्य रूप से गांधी की लिखी किताब हिंद स्वराज पर केंद्रित है। राजनीतिक और आर्थिक शक्ति का विकेंद्रीकरण, प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण और बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण की ओर परंपरागत रूप से अनिच्छा, और साथ ही स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता पर जोर देना गांधीवादी समाजवाद की प्रमुख विशेषताएं हैं। वे बड़े उद्योगों के सख्त खिलाफ थे। उनका कहना था कि हमे ऐसी टेक्नोलॉजी (तकनीक) जरूर चाहिए जी मानव के काम को आसान कर दे किंतु ऐसी मशीनें कत्तई नहीं चाहिए जो मानव जा स्थान ले लें! वे भारत जैसी बड़ी आबादी वाले राष्ट्र हेतु पूंजी प्रधान टेक्नोलॉजी के बजाए श्रम प्रधान टेक्नोलॉजी के प्रबल पक्षधर थे। उनका मुख्य रूप से जीवन एवं समाजोपयोगी शिक्षा के साथ संस्कारों तथा जीवन मूल्यों पर ज्यादा फोकस था। उनका जीवन की संघर्ष यात्रा का लक्ष्य सामाजिक परिवर्तन की धारा को जगाए रख कर अहिंसक विचारों द्वारा समाज में विकृत प्रवृत्तियों का बहिष्कार और तिरस्कार करने का है. ताकि , सद्भाव द्वारा वह आनंद प्राप्त किया जा सके जो परमानंद में परिणत हो जाता है जिसे अनुभूति द्वारा अनुभव किया जा सकता है ,वैभव और विलासिता की तराजू पर मापना संभव नहीं। बापू जी कहा करते थे शहरों के ज्यादा पढ़े लिखे लोगों से गावों के अनपढ़ लोग अच्छे हैं क्योंकि वे ग्रामीण लोग ज्यादा संस्कारित है। उनका कहना था कि स्वराज मिलने पर हम स्वभाषा में शिक्षा देंगे चाहे भले उसके लिए अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने वाली शिक्षा संस्थाओं, विश्विद्यालयों को क्यों न बंद करना पड़े! संसद में 6 महीने से अधिक अंग्रेजी बोलने की अनुमति देने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि स्वराज मिलने के 6 माह बाद संसद में जो अंग्रेजी बोलते मिल जायेगा उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। बापू जी का शांति अहिंसा, अपरिग्रह, शुचिता, रामराज्य, स्वदेशी, स्वाधीनता, स्वरोजगार, स्वराज, ग्राम राज, ग्रामोद्योग, सामाजिक समरसता, कुटीर उद्योग, सत्याग्रह, स्वच्छता , ट्रस्टीशिप, उपवास – प्राकृतिक चिकित्सा आदि के प्रति आग्रह सर्वदा वंदनीय एवं अभिनंदनीय है। वर्तमान परिवेश में, गांधी महात्मा जी के जीवन मूल्य और आदर्श पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं। अपना पूरा जीवन, बापू जी ने खुद को सत्य (सत्याग्रह), अहिंसा, करुणा और दयालुता के अभ्यास के लिए समर्पित कर दिया। वे नित्य नए प्रयोग के लिए जाने जाते थे। बापू जी के विचारों को अपनाना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उनके विचारों को अपना कर सभी आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक समस्याओ से मुक्ति पाया जा सकता है और राष्ट्र को स्वावलंबी, सुखी, संपन्न एवं खुशहाल बनाया जा सकता है।

अमीरों का क्लब है वर्ल्ड इक्नॉमिक फोरम

अश्विनी

जनवरी 15 से 19 के बीच दुनिया के एक महत्वपूर्ण मंच, वर्ल्ड इक्नॉमिक फोरम, का सम्मेलन डावोस (स्विट्जरलैंड) में सम्पन्न हुआ। वर्ष 1971 में अस्तित्व में आया वर्ल्ड इक्नॉमिक फोरम, पिछले लगभग 53 साल से वैश्विक आर्थिक संरचना पर चर्चा करने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था के नाते उभरा है। व्यापार, भू–राजनीति, सुरक्षा, सहकार, ऊर्जा से लेकर पर्यावरण और प्रकृति समेत अनेकानेक मुद्दों पर इस मंच पर चर्चा होती रही है। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र की बड़ी हस्तियों ने डावोस के इस सम्मेलन में भाग लिया। 60 देशों के शासनाध्यक्षों के अलावा बड़ी कई संस्थाओं के प्रतिनिधि, राजनेता, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रमुख, और अनेकानेक आर्थिक जगत के प्रमुख महानुभाव इस सम्मेलन में आयोजित बैठकों और गोष्ठियों में दिखे। 1000 बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा पोषित यह मंच, अपने सम्मेलनों में भाग लेने वालों से मोटी रकम फीस के रूप में लेता है। यानी किसी भी तरह से यह सर्वसमावेषी मंच तो नहीं कहा जा सकता। समाज में कम भाग्यशाली लोगों की ओर से बोलने वालों में से शायद कोई यहां नहीं पहुंच पाता। यह मंच दुनिया की उन विशालकाय कंपनियों की दुनिया का ही मंच कहा जा सकता है, जिनके पैसे से इसका काम चलता है, क्योंकि इसमें दुनिया के सामान्य जन के हित साधने जैसी कोई बात नहीं होती। यदि वर्ष 2024 के ही डावोस में आयोजित वर्ल्ड इक्नॉमिक फोरम की बात करें तो देखते हैं कि 5 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उनका सामान्यजन से कोई खास सरोकार दिखाई नहीं देता। उदाहरण के लिए एक सत्र में इस बात पर चर्चा होती है कि दुनिया में व्यापार और निवेश तथाकथित रूप से कुशल साझेदारी के स्थान पर मित्रता के आधार पर हो रहा है। रूस–यूक्रेन संघर्ष, इजराइल–हमास युद्ध आदि स्थितियां इन कंपनियों के लिए इसलिए शुभ नहीं हैं, क्योंकि इनके कारण उनके निवेश प्रभावित हो रहे हैं, जिनके कारण उनमें चिंता व्याप्त है।

वर्ल्ड इक्नॉमिक फोरम के इस मंच पर जिन 60 शासनाध्यक्षों ने भाग लिया वे सभी वैश्विक भू–राजनीति में उथल–पुथल, देशों के बीच बढ़ती वैमनस्यता और युद्ध की स्थिति से चिंता व्यक्त करते हुए देखे गए। चाहे उनकी चिंता वाजिब है, लेकिन आर्थिकी की चर्चा करते समय उनका ध्यान मुल्कों के बीच असमानताओं और दुनिया में गरीबी, निरक्षरता और बेरोजगारी की तरफ नहीं था। एक विषय पर जिसमें पूरे दुनिया का सरोकार है, यानी पर्यावरण और मौसम परिवर्तन, उस पर बात तो हुई, लेकिन समाधान के लिए वैश्विक नेताओं में कोई विशेष इच्छाशक्ति दिखाई नहीं दी। पिछले कई पर्यावरण सम्मेलनों से यह स्पष्ट हो रहा है कि आज पर्यावरण पर चर्चा से ज्यादा समाधान की जरूरत है। काफी साल पहले विकसित देशों ने यह वादा किया था कि वे हर वर्ष 100 अरब अमरीकी डॉलर की सहायता पर्यावरण समस्या से निपटने के लिए करेंगे। लेकिन वह सहायता कहीं दूर–दूर तक नजर नहीं आ रही। उसी तरह से बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जिनकी संपत्ति खरबों डॉलरों की है, वर्ल्ड इक्नॉमिक फोरम या अन्य मंचों पर पर्यावरण की समस्या पर चाहे चर्चा करती होंगी, लेकिन वे अभी भी अपने पास उपलब्ध प्रौद्योगिकी को भी बिना भारी शुल्क पर्यावरण समस्या से निपटने के लिए साझा करने के लिए तैयार नहीं हैं। यह स्थिति बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के दोहरे चरित्र की ओर इंगित करती है। मुद्दों के प्रति ईमानदारी की कमी रू वे सभी महानुभाव जो डावोस की बैठक में भाग लेने आए, उन्होंने दुनिया में बिगड़ते पर्यावरण और बदलते मौसम के कारण तबाही की आशंकाओं पर चर्चा तो की, लेकिन उनमें से अधिकांश अपने–अपने निजी विमान से वहां आए। उससे कार्बन का कितना उत्सर्जन हुआ और पर्यावरण का कितना ह्रास हुआ, उस ओर वे उदासीन दिखे। यदि वास्तव में वे वर्ल्ड इक्नॉमिक फोरम के कर्ता–धर्ता दुनिया के समक्ष प्रस्तुत मुद्दों के प्रति संवेदनशील होते तो इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारी–भरकम शुल्क की अनिवार्यता नहीं होती। ऊंचे शुल्क के कारण इस सम्मेलन में हाशिये पर खड़े समुदायों, पिछड़े समाजों के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं और सामान्य लोगों को भी इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता। शासनाध्यक्षों और सरकारों में बड़े मंत्रियों और बड़ी कंपनियों के चहेते चुनिंदा बुद्धिजीवियों की उपस्थिति इन कंपनियों के एजेंडे को वैधता प्रदान करती है। महामारी में उजागर हुआ था बड़े कारपोरेट का वीभत्स चेहरा जाहिर है चाहे ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां मानवता और विश्व कल्याण की कितनी भी बातें करें, इनका इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान व्यवहार दानवों को भी लज्जित करने वाला था। फाइजर नामक कंपनी ने तो अप्रभावी वैक्सीन ही जानबूझ कर दुनिया भर में बेच दी। कंपनी को भली भांति मालूम था कि उनकी वैक्सीन प्रभावी नहीं, उसके बावजूद वो अमरीकी सरकार के माध्यम से भारत सरकार भी दबाव बना रही थी। यही नहीं अमरीकी दबाव में भारत की विपक्षी पार्टियां भी सरकार पर इसकी वैक्सीन खरीदने हेतु दबाव बना रही थी। पिछले वर्ल्ड इक्नॉमिक फोरम (2023) में जब पत्रकारों द्वारा फाइजर कंपनी के प्रमुख से इस बाबत जवाब मांगा गया तो वो कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं हुए। यह बात छुपी हुई नहीं है कि 'गैट' समझौतों में अधिकांश समझौते बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दबाव में हुए, ट्रिप्स समझौते में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हित में न केवल दवाओं और चिकित्सीय उपकरणों समेत सभी प्रकार के उत्पादों पर पेटेंट की अवधि बढ़ाई गई, प्रक्रिया पेटेंट से उत्पाद पेटेंट की व्यवस्था भी लागू की गई, जिससे दुनिया के सभी देशों में स्वास्थ्य सुरक्षा बाधित हुई। जब भारत की कैडिला कंपनी से दक्षिण अफ्रीका द्वारा दवाई खरीदने का न कंपनियों ने विरोध किया और इसके कारण उन्हें जनता के रोष का सामना करना पड़ा तो डब्ल्यूटीओ में मान्य किया गया कि महामारी और अपातकालीन परिस्थितियों में पेटेंट अप्रभावी रहेंगे। लेकिन दुनिया ने देखा कि सदी की सबसे भयंकर महामारी के बावजूद बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपने पेटेंट अधिकारों को नहीं छोड़ा। यही नहीं जब भारत और दक्षिण अफ्रीका के नेतृत्व में 100 से अधिक देशों ने ट्रिप्स काउंसिल के सामने 'ट्रिप्स वेवर' यानी ट्रिप्स से छूट का प्रस्ताव रखा तो अपनी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दबाव में अमरीका और यूरोपीय देशों समेत सभी विकसित देशों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। तमाम प्रयासों के बावजूद सिर्फ कोरोना वैक्सीन पर ही उन्होंने पेटेंट के अधिकार को छोडने का प्रस्ताव मान्य किया। लेकिन उसमें भी इतनी शर्तें जोड़ दी गई, जिसके कारण वह छूट लगभग निष्प्रभावी हो गई। समझा जा सकता है कि ऐसे अंतरराष्ट्रीय मंच जिसमें केवल बहुराष्ट्रीय कंपनियों का ही दबदबा हो और जिसमें विश्व के सामान्य प्रतिनिधियों की कोई प्रभावी भूमिका न हो, उससे दुनिया के किसी भी प्रकार के भले की कल्पना नहीं की जा सकती। समझना होगा कि वर्ल्ड इक्नॉमिक फोरम जिसकी विश्व में कोई आधिकारिक भूमिका नहीं है और जो बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों, जिनका धर्म ही लाभ और केवल लाभ कमाना है और जो मानवता के प्रति इतनी अधिक असंवेदनशील है, का ही एक मंच है, उनसे क्या अपेक्षा हो सकती है। ऐसे मंचों से विश्व को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि उनका वास्तविक एजेंडा पारदर्शी नहीं है। अमरीका में भी विरोध रू 19 जनवरी, 2024 को अमरीकी प्रतिनिधि स्कॉट पेरी (पीए–10) ने पांच अन्य लोगों के साथ मिलकर 'डिफंड डावोस एक्ट' पेश किया, और कहा, 'अमरीकी करदाताओं को द्वीपीय, वैश्विक अभिजात्य वर्ग के लिए वार्षिक स्की यात्राओं के लिए धन देने के लिए मजबूर करना बेतुका है निंदनीय तो छोड़ ही देंश विश्व आर्थिक मंच अमरीकी फंडिंग के एक प्रतिशत के लायक भी नहीं है, और यह सही समय है जब हम दावोस को निधि से वंचित कर रहे हैं।' इससे पता चलता है कि अमरीका में भी कांग्रेस द्वारा विरोध किया जा रहा है।

लंका का कानून राजनीतिक असहमति को अपराध घोषित करना चाहता

ललित

श्रीलंका के राजपक्षे अपनी अंकुश और नियंत्रण रणनीति के लिए जाने जाते थे। जनसंख्या को नियंत्रण में रखने के लिए उनके राजनीतिक शस्त्रागार में कई उपकरण थे। महिंदा राजपक्षे के 10 साल के शासन के दौरान, द्वीप का मानवाधिकार रिकॉर्ड एक राष्ट्रीय शर्मिंदगी था। उनके भाई गोटबाया, जो उस समय शक्तिशाली रक्षा सचिव थे, ने कसम खाई थी कि उनके कार्यकाल के दौरान श्रीलंका में सूचना का अधिकार कानून नहीं बनेगा। उन्होंने अपनी बात रखी. 2015 में महिंदा राजपक्षे की अप्रत्याशित हार के बाद ही आरटीआई कानून बनाया गया था। मूल रूप से बहुसंख्यकवादी, कम से कम वे राजनीतिक उदारवादी होने का दिखावा नहीं करते थे जो मानवाधिकारों के पश्चिमी उपदेशों की कम परवाह नहीं कर सकते थे। उन्होंने इस तरह शासन किया जैसे कि जब तक चीन उनके साथ खड़ा था, तब तक विश्व जनमत एक हल्की चिड़चिड़ाहट थी। हंबनटोटा शासक कबीले की पंथ पूजा 2022 से ठीक हो सकती है, और आज, राजपक्षे अत्यधिक अलोकप्रिय हैं और वर्तमान आर्थिक संकट के लिए दोषी हैं। प्रतिस्थापन राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने महत्वपूर्ण क्षण में श्रीलंका के साथ खड़े होने के लिए बहुपक्षीय ऋण देने वाली एजेंसियों को आश्वस्त करने के लिए काम किया है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से बेलआउट प्राप्त किया है। अफसोस की बात है, (हालांकि आश्चर्य की बात नहीं है), इस स्व–घोषित राजनीतिक उदारवादी ने राजपक्षे द्वारा हस्ताक्षरित एक परिचालन शैली अपनाई है। वह असहमति को नियंत्रित करने के लिए तेजी से और निश्चित रूप से आगे बढ़े हैं, पहले ऑफलाइन, इसे कानून और व्यवस्था को बहाल करने की आवश्यकता बताते हुए, और अब ऑनलाइन स्थान को नियंत्रित करने के लिए। यह विक्रमसिंघे ही थे जिन्होंने मैत्रीपाला सिरिसेना प्रशासन में प्रधान मंत्री के रूप में आरटीआई कानून को आगे बढ़ाया था। फिर भी उन्होंने ऑनलाइन अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने के लिए एक कठोर कानून को आगे बढ़ाने में कोई समय बर्बाद नहीं किया, ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक (ओएसबी) को 25 जनवरी को भारी बहुमत के साथ संसद में पेश किया गया। एक दिन बाद, 26 जनवरी को, उन्होंने संसद को दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया, जिससे कोई भी कार्रवाई विफल हो गई। विवादास्पद बिल पर आगे की चर्चा। विधेयक को संसद के माध्यम से जल्दबाजी में पारित किया गया। विरोध प्रदर्शनों के साथ– साथ लोगों की मौलिक स्वतंत्रता को खत्म करने के लिए कुल 52 मामलों ने इसे सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी। विक्रमसिंघे को राजपक्षे के राजनीतिक हितों का विस्तार माना जाता है क्योंकि उनका अस्तित्व श्रीलंका पोडुजाना पेरामुना (एसएलपीपी) के समर्थन से जुड़ा है। नए कानून को दोहरे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक उपकरण के रूप में देखा जाता हैरू पारिवारिक शासन को समाप्त करने के लिए राजपक्षे को हटाने के लिए अभियान चलाने वाले राजनीतिक असंतुष्टों को कुचलने का एक प्रतिशोधपूर्ण प्रयास और एक महत्वपूर्ण चुनावी वर्ष में असंतोष को दफनाने के लिए एक कानूनी उपकरण। विधेयक को जल्द ही संसद अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किया जाएगा, जिससे यह कानून बन जाएगा, और ओएसबी राजनीतिक शस्त्रागार में ऑनलाइन चुप्पी को नियंत्रित करने के लिए नया उपकरण होगा, खासकर इस चुनावी वर्ष में। अब जबकि यह सच हो गया है, सरकार का तर्क यह है कि ओएसबी का उद्देश्य साइबर अपराधों से निपटना और समाज के कमजोर वर्गों की रक्षा करना है। नया अधिनियम एक ऑनलाइन सुरक्षा आयोग को व्यापक शक्तियां प्रदान करता है जो यह निर्धारित कर सकता है कि "निषेधात्मक बयान" क्या हैं और ऐसी सामग्री को हटाने और अपराधी माने जाने वाले लोगों की पहुंच को अक्षम करने के लिए इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को सिफारिशें कर सकता है। इसमें गूगल, फेसबुक जैसे सेवा प्रदाताओं को उनके प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की गई सामग्री के लिए जवाबदेह ठहराने का प्रावधान है। राष्ट्रपति विक्रमसिंघे और अप्रिय विधेयक के जनक, सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री तिरान एलेस ने दावा किया है कि यह कानून मीडिया की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का प्रयास नहीं है, बल्कि साइबर अपराध, डेटा चोरी और डिजिटल धोखाधड़ी को रोकने के लिए एक कदम है। पूर्व राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना को आत्म–बधाई वाले स्वर में यह कहते हुए सुना गया कि सोशल मीडिया द्वारा भड़काई गई हिंसक स्थिति को नियंत्रित करने के लिए उन्हें सोशल मीडिया को एक सप्ताह के लिए बंद करना पड़ा। लेकिन श्रीलंका की मौजूदा हकीकत अलग है. यह आर्थिक पतन के कगार पर है। आईएमएफ ने भले ही एक जीवनरेखा की पेशकश की है लेकिन आर्थिक सुधार के लिए एक वास्तविक रोडमैप अभी तक सामने नहीं आया है। श्रीलंका के लिए मौजूदा वित्तीय संकट से उबरने और जर्जर अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करने से बड़ी कोई प्राथमिकता नहीं हो सकती है। इसके लिए सर्वदलीय सहमति और अपार प्रयास की आवश्यकता है। लेकिन दुख की बात है कि अपने देश को चलाने में नाकाम रहने और इसे निराशा की ओर धकेलने के बाद राजनेताओं की नजर अगले चुनाव पर है। यह संभवतः दक्षिण एशियाई राजनीतिक अस्वस्थता है कि हमारे शासन का सूत्र सख्ती से शासन करना और सार्वजनिक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मौलिक स्वतंत्रता को नियंत्रित करना है। विक्रमसिंघे भी इसी मॉडल का अनुसरण करते हैं। उन्होंने पद संभालते ही अपना चाबुक चलाया और देश में 'सामान्य स्थिति' की पेशकश के तहत वैध असंतोष को कुचल दिया। वह असहमति को मिटाने और प्रदर्शनकारियों पर नकेल कसने के लिए बल प्रयोग करने में लगातार लगे हुए हैं।

जीवन निर्माण की दिशा तय करता है रोवर रेंजर्स प्रशिक्षण - प्रो.अजय दुबे

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर तिलकधारी महाविद्यालय जौनपुर के क्रीड़ा मैदान में पंच दिवसीय रोवर्स रेंजर्स प्रशिक्षण शिविर के तीसरे दिन मुख्य वक्ता रूप में संबोधन करते हुए टी.डी. कॉलेज बी.एड. विभाग के विभागाध्यक्ष एवं वी.ब. सिंह पूर्वांचल विद्यालय रोवर्स रेंजर्स जिला कमिश्नर प्रोफेसर अजय कुमार दुबे ने कहा कि रोवर रेंजर्स के द्वारा जीवन निर्माण की दिशाएं निर्धारित होती हैं रोवर्स रेंजर्स का उद्देश्य जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं का समाधान कर जीवन का निर्माण करना है। जीवन निर्माण की विद्या अध्यापक और अनुशासित छात्र के साथ ही संभव है वर्तमान में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है कि पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का आयोजन प्रत्येक महाविद्यालय में समय–समय पर और निश्चित रूप से होना चाहिए। रोवर्स रेंजर्स की संयोजक प्रोफेसर श्रद्धा सिंह ने कहा कि प्रशिक्षण द्वारा हमें सीख मिलती है कि अच्छाइयों के प्रति हमारी गहरी निष्ठा हो। विचार और आचरण से भी नेक बनना अपना उद्देश्य हो । मुख्य अनुशास्ता प्रोफेसर रीता सिंह ने कहा। कि अनुशासित व्यवहार द्वारा ही हम अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। डॉ गीता सिंह ने कहा कि भले ही इसमें हमें तात्कालीक असफलता मिले लेकिन हमें सत्य और ईमानदारी के साथ कार्य करते रहना है। डॉ माया सिंह ने कहा कि आवश्यकता इस बात की है कि समस्त छात्र अपने अंदर रोवर रेंजर्स भावना का समावेश करें और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहें डॉ विपिन कुमार सिंह ने कहा कि आज के छात्र कल के योग नागरिक हैं इसीलिए आवश्यकता है कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करते रहना चाहिए। डॉ देवेंद्र सिंह ने कहा कि यह आवश्यक है कि हम अपने दिन प्रतिदिन के व्यवहार में पर्यावरण समाज जागरूकता और एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना को करते रहे। रोवर्स रेंजर्स के पंच दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में छात्र छात्राओं को गांठें बंधन, व्याख्यान, पोस्टर, निबंध ,मार्च पास्ट आदि गतिविधियों को सिखाया गया । प्रशिक्षण शिविर को संपन्न कराने में प्रशिक्षक राकेश कुमार मिश्रा, ज्ञान चंद चौहान, ,अजय चौहान, नितेश प्रजापति, निसार अहमद, प्रीति मिश्रा आदि ने विभिन्न कौशलों की जानकारी प्रदान किया।

दो बसों की आमने सामने टक्कर, चालक की मौत, कई यात्री घायल

ब्यूरो रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव

'पाली(हरदोई)'। थाना क्षेत्र के ग्राम गोपालपुर के पास रोडवेज बस और प्राइवेट बस की आमने–सामने टक्कर हो गई। जिसमें दोनों बसों के परखच्चे उड़ गए। दोनों बसों के चालकों को गंभीर अवस्था में शाहाबाद सीएचसी भेजा गया जिसमें एक चालक की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह को रोडवेज बस (चालक राजीव कुमार) पाली से शाहाबाद की तरफ जा रही थी तभी पाली थाना क्षेत्र में गोपालपुर गांव के पास सामने से आ रही डबल डेकर प्राइवेट बस से रोडवेज बस की आमने सामने टक्कर हो गई जिसमें दोंनो बसें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गयीं। गाड़ी में फंसे रोडवेज बस चालक राजीव कुमार को किसी तरह पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला और इसी तरह डबल डेकर प्राइवेट बस के चालक को भी बाहर निकाला गया। आनन फानन में दोनों चालकों समेत अन्य घायल सवारियों को अस्पताल भेजा गया। इस संबध पाली थाना प्रभारी निरीक्षक अरविंद कुमार राय ने बताया कि डबल डेकर प्राइवेट बस के चालक की मौत हो गई है। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। स्थानीय पुलिस ने किसी तरह भीड़ को सड़क से हटाकर यातायात बहाल कराया है।

केन्द्रीय बजट 2024 से अपेक्षाएं - (डा.) विक्रमदेव आचार्य

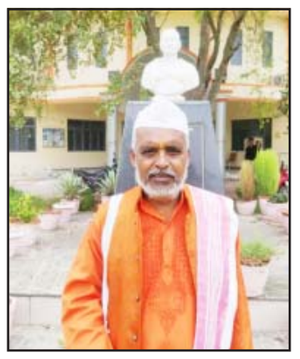

क्राइम रिपोर्टर
धनन्जय विश्वकर्मा

जौनपुर। आगामी केंद्रीय बजट पर वीर बहादुर सिंह पुर्वांचल विश्वविद्यालय के डा विक्रम देव आचार्य ने कहा कि आगामी केंद्रीय बजट राष्ट्र में निवेश और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए. भारत सरकार का बढ़ता कर्ज भी खतरा नहीं बल्कि वित्तीय अनुशासन सहित आधारभूत संरचनाओं के विकास हेतु यह अनिवार्य है। अमेरिका, जापान आदि विकसित राष्ट्रों के ऊपर भारतीय जीडीपी के अनुपात में अधिक कर्ज का बोझ है। भारत गांवों का देश कहा जाता है। भारत की आत्मा गांवों में बसती है। गांवों की उत्पत्ति गावरू से हुई है जिसका अर्थ होता है जहां बड़ी संख्या में गाय (गोवंश) रहती हों और जहां की आजीविका एवं पूरी संस्कृति गोवंश पर निर्भर हो। भारत जब सोने की चिड़िया एवं विश्व गुरु था तब, ष्उत्तम खेती मध्यम बान! निषिद्ध चाकरी भीख निदान!!ष् की कहावत प्रचलित थी। जिसे फिर से सार्थक करने की जरूरत है। इसके लिए श्रम एवं गऊ सेवा के प्रति निष्ठा उत्पन्न करने की बहुत जरूरत है। एंटी भू माफिया टास्क फोर्स द्वारा गोचर, वनभूमि , झील, नदियों एवं जलाशयों को कब्जों से मुक्त कराकर उनका सही उपयोग हो। हर गांव के गोचर भूमि में सर्वोच्च प्राथमिकता पर गोशाला का निर्माण हो। गोबर से गोबर गैस, सीएनजी, ऑर्गेनिक खाद, पेंट, वैदिक प्लास्टर, ईट, साबुन, धूप बत्ती आदि का निर्माण हो। ग्राम केंद्रित, गऊ आधारित संधृत विकास मॉडलष् में पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के 'PURA मॉडल' (विकास खंडों को क्लस्टर्स में बांटकर योजनबद्ध विकास की रणनीति बनाने) को शामिल कर सम्यक रूप से ग्रामीण विकास की ठोस रणनीति बने।

अर्थ क्रांति (जीएसटी , आयकर सहित सभी प्रत्यक्ष – परोक्ष कर समाप्त कर बीटीटी यानि बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स लाकर) बड़ा क्रांतिकारी टैक्स रिफार्म सहित टवै मॉडल (विलेज सेंट्रिक डेवलपेंट स्ट्रैटजिक मॉडल) को अपनाने से भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने में बहुत सहायता मिलेगी! 100% डिजिटल ट्रांजेक्शन सहित बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स लाने से जीएसटी एवं आयकर में होने वाली कर चोरियां रुकेंगी और सरकार को 4 गुना से अधिक राजस्व की प्राप्ति होगी। जिस प्रकार जीएसटी में ध्20 लाख के ट्रांजेक्शन पर कोई टैक्स रिटर्न नहीं भरना है। वैसे ही बीटीटी में भी प्रावधान हो कि ध्20 लाख तक कोई टैक्स नहीं। इस मुद्दे पर अर्थक्रांति के विशेषज्ञों से वार्ता हो।

लोक सभा चुनाव 2014 के पूर्व तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज की अध्यक्षता में वर्तमान प्रधान सेवक श्री नरेंद्रमोदी सहित भाजपा के शीर्षस्थ नेताओं एवं अर्थ तथा वित्त विशेषज्ञों की उपस्थिति में निर्णय लिया गया था कि आयकर सहित सभी प्रकार के टैक्स समाप्त करके केवल एक बीटीटी लाया जाएगा। किंतु अभी तक ऐसा नहीं हो सका। आयकर बंद होने से बचत एवं निवेश में बहुत तेज वृद्धि होगी और देश बहुत तीव्र गति से विकास करेगा। गौ अर्थशास्त्र (काउनॉमिक्स) , अवश्यकता का अर्थशास्त्र (नीडोनोमिक्स), गांधीवादी अर्थनीति (गांधींनॉमिक्स) गो विज्ञान, डेयरी उत्पाद (विज्ञान) , हार्टिकल्चर, फ्लोरीकल्चर आदि के विषय विशेषज्ञों के साथ मा0 प्रधान मंत्री, मा0 वित्त मंत्री एवं भारत सरकार के आर्थिक तथा वित्तीय सलाहकारों को बैठकर वार्ता करके ठोस रणनीति बनाकर ऐसा 'ग्राम केंद्रित स्वदेशी संधृत आर्थिक विकास मॉडल' बने जो लोक कल्याणक एवं विकास को तेज गति देने वाला हो। कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र के रणनीतिक एवं संधृत विकास हेतु अधिक धन के आवंटन और कृषि ऋण सहित पीएम विश्वकर्मा योजना के ऋण पर ब्याज को 4: से भी कम करने की जरूरत है। ग्रामीण प्रबंधन, ग्रामीण विकास, ग्रामीण अर्थशास्त्र सहित ग्रामीण एवं महिला उद्यमशीलता, खाद्य (अन्न, फल एवं साग सब्जियों) प्रसंस्करण सहित गोपालन, गोबर गो–मूत्र एवं गौ– दुग्ध आदि के नवोन्मेषी प्रसंस्करण, मधुमक्खी पालन, श्री अन्न सहित फल, शाक सब्जियों के उत्पादन आदि की शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखकर उसे विवि से विद्यालय स्तर पर पढ़ने– पढ़ाने पर जोर दिया जाय। उन्हे विधिवत पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाए। अंग्रेजों द्वारा प्रारंभ की गई स्कूल (इशकुल) प्रणाली बंदकर भारतीय वैदिक संस्कारों से युक्त गुरुकुल के रूप में विकसित किया जाए तब भारतीय (राष्ट्रीय) शिक्षा नीति ठीक ढंग से क्रियान्वित हो सकेगी। यदि उपरोक्त सुझावों को पर आधारित आर्थिक नीतियां सरकार बनाए तो भारत बहुत जल्द सोने का शेर एवं विश्व गुरु बन सकेगा।

समर्पण इंस्टीट्यूट में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने किया तीन दिवसीय "आत्मरक्षा कार्यशाला" का शुभारम्भ

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। समर्पण इंस्टीट्यूट आफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज एवं समर्पण कॉलेज आफ फार्मेसी संस्थान के समर्पण लॉन में तीन दिवसीय "आत्मरक्षा कार्यशाला" का आयोजन किया जा रहा है। जिसका उदघाटन जय वीर सिंह , कैबिनेट मंत्री, पर्यटन एवं संस्कृति, उ0प्र0 सरकार द्वारा किया गया। कार्यशाला में विशिष्ट अतिथि योगेश शुक्ला , विधायक बी0के0टी0, आत्म प्रकाश मिश्रा , निदेशक दूरदर्शन, नरेन्द्र भदौरिया , विशेष अतिथि पुनीत अवस्थी , निदेशक डॉ0 आशा स्मृति महाविद्यालय, प्रो0 प्रीति पाण्डेय, आत्मरक्षा प्रशिक्षक की उपस्थिति रही। मंत्री जी द्वारा सर्वप्रथम समर्पण अस्पताल में अस्पताल संचालक मनीष मिश्रा एवं ऑपरेशन मैनेजर आशीष दुबे की उपस्थिति में अस्पताल का भ्रमण किया गया तथा भर्ती मरीजों को फल वितरित किया गया। तदोपरान्त मैनेजर ए0के0 पाठक द्वारा मंत्री जी को मंदिर में पूजा अर्चना कराई गयी। संस्थान के नर्सिंग कालेज की प्रधानाचार्या एवं फार्मेसी कालेज के प्रधानाचार्य की उपस्थिति में मंत्री जी द्वारा दोनों संकायों का निरीक्षण किया गया। जिसके पश्चात संस्थान के निर्मल ऑडीटोरियम में संस्थापक प्रो0 डॉ0 आर0एस0 दुबे द्वारा मुख्य अतिथि एवं समस्त गणमान्य अतिथियों का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। डायरेक्टर दूरदर्शन आत्म प्रकाश मिश्रा द्वारा बताया गया कि 500 वर्षों की कठिन तपस्या के पश्चात आज भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण हुई है जिससे आज भारत का प्रत्येक सनातनी सनातन के बारे में निःसंकोच बात कर सकता है और अपने समाज तथा परिवार को सनातन के बारे में बता सकता है। लेखक नरेन्द्र भदौरिया द्वारा बताया गया कि श्री राम मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रतिष्ठित की गयी तथा प्रभु श्री राम जी के गर्भ ग्रह में जाने पर एक अलौकिक शक्ति की अनुभूति होती है तथा प्रतिष्ठा के पश्चात भगवान की मूर्ति में एक परिवर्तन देखने को मिला जिसमें प्रभु राम के चेहरे पर अलग ही मुस्कुराहट प्रतीत होती है।

विशिष्ट अतिथि बीकेटी विधायक योगेश शुक्ला द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा अपने परिक्षेत्र से लाखों की संख्या में भगवान श्री राम का दर्शन करने हेतु निःशुल्क आवागमन का प्रबन्ध किया जिससे श्रद्धालुओं ने हर्षोल्लास के साथ अयोध्या जाकर दर्शन किया। मुख्य अतिथि मा0 जय वीर सिंह जी द्वारा संस्थान में "आत्मरक्षा कार्यशाला" एवं गोष्ठी "हे श्री राम" के बारे में विस्तार से बताया गया कि आज प्रत्येक महिला संस्थान में प्रत्येक छात्रा को अपनी रक्षा में आत्मरक्षा करने का पूर्ण अधिकार है और वह इस क्षेत्र में तीव्रता से अपने कदम बढ़ा रही हैं। इस कार्यशाला से इस संस्थान की प्रत्येक छात्रा अपनी आत्मरक्षा के लिए प्रेरित होगी और वह समाज में बिना डरे हुए निःसंकोच कहीं भी आ जा सकती है। संस्थान की प्रधानाचार्या डॉ0 दीप्ति शुक्ला ने मुख्य अतिथि एवं समस्त गणमान्य अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए संस्थान में आयोजित कार्यशाला एवं गोष्ठी को अपने कुशल मार्गदर्शन में सफलता के चरम पर पहुँचाया।

भाजपा का गांव चलो अभियान फरवरी 4 से 11 तक, लोक सभा चुनावों से पहले जमीन दुरुस्त करने को कसी कमर

हरदोई (अंबरीष कुमार सक्सेना) भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में जनपद की दो लोकसभा सीटों को जीतने की रणनीति बनाते हुए गांव चलो अभियान शुरू किया। इस अभियान की कार्यशाला भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित हुई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि जिला प्रभारी शंकर लाल लोधी लोकसभा प्रभारी हरदोई दिनेश दुबे और मिश्रिख लोकसभा प्रभारी रामनिवास यादव प्रमुख रूप से उपस्थित रहें। अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन ने की कार्यशाला में जनपद के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया, जिसमें सभी मंडल प्रभारी मंडल अध्यक्ष, सभी मंडल विस्तारक तथा मोर्चा के पदाधिकारी उपस्थित रहे। गांव चलो अभियान के अंतर्गत हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी प्रवासी के रूप में गांव में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई योजनाओं की जानकारी देंगे तथा लाभार्थियों से वार्ता कर पार्टी के समर्थन में जनता के मंतव्य को लामबंद करेंगे। अभियान को भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन और जिला प्रभारी शंकर लाल लोधी के नेतृत्व में आयोजित होगी। कार्यशाला में जिला प्रभारी शंकर लाल लोधी ने बताया कि लोकसभा 2024 का चुनाव नतीजा देश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जायेगा। उन्होंने बताया कि 2024 में जनता के अभूतपूर्व आशिर्वाद से नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भाजपा की केंद्र में तीसरी बार प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रही है। भाजपा की जनकल्याण नीतियों और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित सभी वर्ग भाजपा को मजबूत करने के लिए लालायित है। भाजपा का गांव चलो अभियान का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि समाज के हर व्यक्ति को पार्टी की नीतियों और नरेंद्र मोदी की विकास यात्रा से जोड़ा जाए। 80 करोड़ से ज्यादा लोग मुफ्त अनाज योजना से लाभान्वित हो रहे है। पिछले 10 वर्षों में महिलाओं के लिए जो काम पार्टी ने किए है उसका फल है कि सभी क्षेत्रों में महिलाओं को आगे बढ़ने का भरपूर मौका मिला। गांव से लेकर शहर तक ऐसा भय मुक्त वातावरण और सशक्त कानून व्यवस्था का निर्माण किया कि महिला अपराध में बड़ी संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश और देश चौमुखी विकास की ओर अग्रसित है। कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए जिलाध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि गांव चलो अभियान की जो कार्यशाला आयोजित हुई है इसका उद्देश्य गांव की आबादी के हर एक व्यक्ति को भाजपा परिवार से जोड़ना है। सभी कार्यकर्ताओं को यह समझना होगा यही समय है और सही समय है जब हम सब मिलकर निष्काम भाव से पार्टी को जिताने के लिए लगना होगा। जिलाध्यक्ष ने कहा कि जनता मोदी की गारंटी पर विश्वास रखती है। मोदी ने जो कहा वो करके दिखाया। राममंदिर की आधारशिला भी उन्होंने रखी और उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी उनकी उपस्थिति में हुई। यह दृश्य देखकर पूरा देश रसमय होगया था। देश के विकास से जुड़ी कोई भी योजना हो अगर प्रधानमंत्री ने उसकी नींव रखी है तो उदघाटन भी वही करते है। इसीलिए जनता को मोदी पर विश्वास है। कार्यशाला को हरदोई लोकसभा प्रभारी दिनेश दुबे एवं मिश्रिख लोकसभा प्रभारी रामनिवास यादव ने भी संबोधित किया। संचालन अभियान प्रमुख तथा जिला मंत्री अजय शुक्ला ने किया। कार्यशाला में प्रमुख रूप से सवाजपुर विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू मिश्रिख लोकसभा संयोजक एवं डीसीबी अध्यक्ष अशोक सिंह पूर्व जिला अध्यक्ष राम बहादुर सिंह रामकिशोर गुप्ता गुड्डू विद्याराम वर्मा अनुसूचित मोर्चा क्षेत्रीय महामंत्री पीके वर्मा जिला उपाध्यक्ष राजेश अग्निहोत्री कर्मवीर सिंह चौहान एसपी मौर्य संदीप सिंह संजय सिंह गुड्डू प्रीतेश दीक्षित श्रवण कनौजिया महामंत्री अनुराग मिश्रा ओम वर्मा सत्येंद्र राजपूत जिला मंत्री अविनाश पांडे बागीश सिंह जय देवी राजपूत मंगतराम नीतू चंद्रा कोषाध्यक्ष डॉ अनुज गुप्ता मीडिया प्रभारी गांगेश पाठक प्रचार मंत्री संदीप अवस्थी कार्यालय मंत्री अतुल सिंह सह मीडिया प्रभारी परेश गुप्ता आईटी संयोजक सौरभ सिंह गौर सोशल मीडिया संयोजक प्रद्युम्न आनंद मिश्रा लक्ष्मी राजपूत मोर्चों के जिला अध्यक्ष एवं मंडलों के अभियान संयोजक मौजूद रहे।

कार्बन उत्सर्जन को कम करने एवं नवीकरणीय ऊर्जा को बढावा देने के लिए सेमिनार का आयोजन

इस अवसर पर एसोसिएटेड चौम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री ऑफ यू.पी. और यूपी सोलर पावर डेवलपमेंट एसोसिएशन के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

हमारे देश में प्रचुर मात्रा में सौर ऊर्जा संसाधन मौजूद हैं और इसका अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए

सरकार सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए लोंगों प्रोत्साहित कर रही है और प्रोत्साहन भी दे रही –डा0 अरूण कुमार सक्सेना

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कार्बन उत्सर्जन को कम करने एवं नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए आज एसोसिएटेड चौम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री ऑफ यू.पी. द्वारा एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमीनार में प्रदेश के वन एवं पर्यावरण, प्राणि उद्यान तथा जलवायु परिवर्तन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डा0 अरूण कुमार सक्सेना मुख्य अतिथि थे। गोमती स्थित एक होटल में आयोजित सेमीनार के दौरान एसोसिएटेड चौम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री ऑफ यू.पी. और यूपी सोलर पावर डेवलपमेंट एसोसिएशन ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए संयुक्त रूप से काम करने और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस मौके पर वन मंत्री ने एसोसिएटेड चौबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ यूपी की पहल की सराहना करते हुए कहा कि हमारे देश में प्रचुर मात्रा में सौर ऊर्जा संसाधन मौजूद हैं और इसका अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए। सरकार सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए लोंगों प्रोत्साहित कर रही है और प्रोत्साहन दे रही है। इससे कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा और अंततः पर्यावरण की रक्षा होगी। उन्होंने पूपी सोलर पावर डेवलपमेंट एसोसिएशन को उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जन अभियान चलाने की सलाह दी। उन्होंने घरों, उद्योगों एवं किसानों द्वारा सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक प्रयोग किए जाने पर बल दिया । उन्होंने बताया कि गलोबल वार्मिंग को नियंत्रण करने में भारत सरकार द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है इससे प्रधानमंत्री का पूरे विश्व में सम्मान बढ़ा है। यूपी नेडा के वरिष्ठ परियोजना अधिकारी राकेश अग्रवाल ने विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी एवं नेडा द्वारा हर सम्भव मदद का आश्वासन दिया । उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के श्री लाल ने प्रदूषण नियंत्रण हेतु बोर्ड द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के ऊपर प्रकाश डाला। तारिक हसन नकवी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ यूपी ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने में नवीकरणीय ऊर्जा की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सूर्योदय योजना की घोषणा की है। इसी कड़ी में दोनो एसोसिएशन ने माननीय प्रधान मंत्री के मिशन का समर्थन करने लिए बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा विकास योजना शुरू की है। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों तक सौर मिशन पहुंचाने के लिय की गई विभिन्न पहलों का भी वर्णन किया है। श्री नकवी ने आश्वासन दिया है कि एसोसिएशन राज्य सरकार के साथ मिलकर मिशन 2027 तक 22000 मेगावाट का लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर काम करेंगे। इस अवसर पर सोलर कमेटी के अध्यक्ष अजय सक्सेना, यूपीएसपीडए के अध्यक्ष अविनेश चौहान, उपाध्यक्ष पवन अग्रवाल एवं सोलर कम्पनियों के प्रतिनिधि इत्यादि अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

सामूहिक दुष्कर्म के अभियुक्तों को 30-30 साल की सजा

गोरखपुर, संवाददाता। रेलवे स्टेशन पर युवती से सामूहिक दुष्कर्म के तीन अभियुक्तों को सोमवार को सिविल कोर्ट से 30–30 साल की सजा सुनाई गई। तीनों पर 50–50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। 17 महीने में कोर्ट से पीड़िता को इंसाफ मिला है। इस मामले में जीआरपी ने साक्ष्यों के साथ सात दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल की थी। एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाने के लिए पत्र भेजा था। अब कोर्ट ने तीनों अभियुक्तों को सजा सुना दी है। जानकारी के मुताबिक, सात सितंबर 2022 की रात धर्मशाला पुल के नीचे तीन युवकों ने मिलकर महाराजगंज की युवती से सामूहिक दुष्कर्म किया था। घटना के बाद खून से लथपथ पीड़िता पैदल ही जीआरपी थाने पहुंची थी। पुलिस ने केस दर्ज किया तो पता चला कि महाराजगंज की रहने वाली युवती घर से नाराज होकर गोरखपुर आई थी। यहां धर्मशाला के आस–पास ही युवती रह रही थी। सात सितंबर की रात युवती को रेलवे स्टेशन पर धर्मशाला पुल के नीचे झाड़ियों में ले जाकर तीन युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। तत्परता दिखाते हुए पुलिस ने इस घटना के आरोपियों सलेमपुर निवासी राजा अंसारी उर्फ इम्तियाज, बशारतपुर निवासी संतोष चौहान और बेगूसराय बिहार निवासी अंकित पासवान को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने जांच कर सात दिन के भीतर 14 सितंबर 2022 को चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। साथ ही तीनों आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की थी। इस चर्चित मामले में सरकारी अधिवक्ता और पुलिस की पैरवी की मदद से महज 17 माह से भी कम दिनों में ही अभियुक्तों को कोर्ट की ओर से सजा सुनाई गई।

बचाव के अधिवक्ता ने कम उम्र का दिया हवाला

अभियुक्तों को बचाने के लिए उनके अधिवक्ता ने तर्क दिया था कि अभियुक्तगण नवयुवक हैं और यह उनकी पहली गलती है, इनके ऊपर परिवार के खर्चे की जिम्मेदारी भी है। पकड़े जाने के बाद पहले दिन से अब तक सभी अभियुक्त जेल की सजा काट रहे हैं, अभियुक्तों में राजा अंसारी उर्फ इम्तियाज 22 वर्ष, बशारतपुर निवासी संतोष चौहान 21 वर्ष और बेगूसराय बिहार निवासी अंकित पासवान की उम्र लगभग 19 वर्ष है।

सामूहिक विवाह में बिना दूल्हे के दुल्हनों की कराई शादी

बलिया, संवाददाता। बलिया जिले के मनियर में 25 जनवरी को आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को लेकर जमकर किरकिरी हो रही है। विवाह समारोह में मौजूद महिलाओं के वर अनुपस्थिति में स्वयं ही अपने गले में वरमालाएं डालने का वीडियो वायरल होने से मामला चर्चा का विषय बना है। रामपुर, घाटमपुर, छितौनी आदि कई गांवों की ऐसी कन्याओं को बुलाया गया था जिनकी शादी, एक या दो वर्ष पहले हो चुकी है। यहां तक कि मुस्लिम कन्याओं को फेरे दिलवा दिए गए थे। हालांकि योजना से संबंधित धनराशि अभी कन्याओं के खाते में हस्तांतरित नहीं की गई है। सीडीओ ओजस्वी राज ने मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया। कमेटी ने गांवों में जाकर जांच भी शुरू कर दी है। फर्जी लाभार्थियों के खिलाफ समाज कल्याण अधिकारी की ओर से मनियर थाने में तहरीर भी दी गई है। समाज कल्याण विभाग से संचालित शादी अनुदान योजना की तरह धीरे–धीरे मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना भी भ्रष्टाचार का शिकार होने लगी है। हालांकि सरकार की ओर से इस वर्ष आवेदन से लेकर धन जारी करने तक की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है।

मिल्कीपुर में किसान की बेटी बनी डिप्टी जेलर

पहले ही प्रयास में हुआ चयन, आईएएस बनने का है सपना

(डाक्टर अजय तिवारी
जिला संवाददाता)

अयोध्या। हमारी बेटियां किसी से कम नहीं है।बेटियां हर क्षेत्र में सफलता के नये आयाम रच रही है।कुछ इसी तरह का उदाहरण अयोध्या के मिल्कीपुर तहसील क्षेत्र स्थित कौराह पूरे गुलाम गांव में भी देखने को मिल रहा है। यूपी लोक सेवा आयोग ने हाल ही पीसीएस परीक्षा 2023 का रिजल्ट जारी किया है। जहां अमानीगंज की प्रगति उपाध्याय ने यूपीपीसीएस परीक्षा 2023 में 41वीं रैंक हासिल की है। बेटी प्रगति उपाध्याय का चयन डिप्टी जेलर के पद पर हुआ है यूपीपीसीएस में चयन होने के बाद उनके परिवार में खुशी की लहर है रिश्तेदार, पड़ोसी आदि उन्हे बधाइयां देने के लिए उनके घर पहुंच रहे हैं। बेटी प्रगति उपाध्याय कड़ी मेहनत और लगन से पहले ही प्रयास में यूपीपीसीएस परीक्षा में सफलता हासिल कर अपनी प्रतिभा साबित की है। इसके साथ ही उन्होंने धर्मनगरी अयोध्या को भी गौरवान्वित किया है और क्षेत्र का मान बढ़ाया है। यूपी पीसीएस वर्ष 2023 में डिप्टी जेलर के पद पर चयनित 23 वर्षीय प्रगति शुरू से ही मेधावी छात्र रही है। इन्होंने हाई स्कूल तक की पढ़ाई हौसिला प्रसाद स्मारक इंटर कॉलेज सिधारी बाजार से की है। इसके बाद संत भीखा दास रामजस महाविद्यालय मोहाली खण्डासा से इंटर एमएससी की पढ़ाई पूर्ण कर ली है। पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने पैतृक गांव तथा लखनऊ में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी।इनका सपना आईएएस अधिकारी बनना है। प्रगति के पिता पवन कुमार उपाध्याय एक किसान तथा प्राइवेट शिक्षक है, इनकी माता रीता उपाध्याय गृहणी है। प्रगति सबसे बड़ी है इनका सेलेक्शन डिप्टी जेलर के पद पर हुआ है तथा इनसे छोटे भाई शिवेंद्र उपाध्याय, उज्जल उपाध्याय, अविरल उपाध्याय 3 भाई तथा छोटी बहन साक्षी अभी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। कुमारगंज बाजार मालिक एवं भाजपा नेता विजय उपाध्याय ने प्रगति उपाध्याय के घर पहुंच कर प्रगति का मुंह मीठा कराते हुए सम्मानित किया। तथा लोगों से बताया कि प्रगति मेरी नातिन भी है। बहुत खुशी की बात है कि पहले ही प्रयास में डिप्टी जेलर के पद को हासिल कर लिया। इस मौके पर रामफूल गोस्वामी अरुण गोस्वामी कमल उपाध्याय सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

लोकसभा चुनाव में मिल्कीपुर सपा विधायक अवधेश अयोध्या पर अखिलेश यादव ने जताया भरोसा

सात बार रह चुके मंत्री व नौवीं बार बने विधायक अवधेश प्रसाद को अयोध्या लोकसभा पीडीए समान्य सीट से बनाया उम्मीदवार

(डाक्टर अजय तिवारी
जिला संवाददाता)

अयोध्या। समाजवादी पार्टी ने फैजाबाद लोकसभा सीट (अयोध्या) सीट से अवधेशप्रसाद को उम्मीदवार बनाकर बड़ा दांव खेला है।पिछड़ा, दलित व अल्पसंख्यक (पीडीए) के अवधेश प्रसाद वह चेहरे हैं जिसे भाजपा के हिंदुत्व वाली प्रयोगशाला अयोध्या की सामान्य सीट से अनुसूचित जाति का प्रत्याशी बना चुनौती दी है।पीडीए का यह समीकरण पाटी के लिए हिंदुत्व की प्रयेगशाला में कितना कारगर होगा, यह तो चुनाव परिणाम से तय होगा।अगर मानें तो फिलहाल अवधेश की उम्मीदवारी से उसे चुनौती दी है।लोकसभा उम्मीदवार बने अवधेश पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के अलावा नौवीं बार विधानसभा में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।पहली बार 1977 में जनता पार्टी से निर्वाचित हुए।उनके राजनीतिक कद का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जनता पार्टी, मुलायम सिंह यादव व अखिलेश यादव सरकार में छह बार मंत्री रहे।सात बार सोहावल विधानसभा सीट (सुरक्षित) वह निर्वाचित हो चुके हैं।सोहावल विधानसभा सीट परिसीमन में बीकापुर होने के बाद उनको मिल्कीपुर (सुरक्षित) सीट पर किस्मत आजमाने के लिए जाना पड़ा।दूसरी बार उस सीट से विधानसभा में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।2004 में उनकी पत्नी सोना देवी जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं।अवधेश प्रसाद बड़े जनाधार वाले व जिले की राजनीति में उनकी पहचान गैर विवादित नेता मे गिनती की जाती हैं।जिस फैजाबाद सीट से पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया है, उसमें उनका पुराना विधानसभा क्षेत्र सोहावल व नया विधानसभा क्षेत्र जहां से विधानसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं मिल्कीपुर उसी में आता है।लोकसभा क पांच में से दो विधानसभा सीट वाले क्षेत्र पर उनकी मजबूत पकड़ है। पीडीए के साथ ही दो विधानसभ क्षेत्रों में उनकी मजबूत पकड़ ही सामान्य सीट पर उनकी उम्मीदवारी का आधार बनी। अवधेश प्रसाद की उम्मीदवारी के साथ पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती सेन परिवार को अब मनाने की होगी।वही मित्रसेन यादव तीन बार अलग–अलग दलों से सांसद चुन जा चुके हैं।उनके निधन के बाद पार्टी ने पुत्र आनंदसेन यादव को पिछले चुनाव में उम्मीदवार बनाया था। वह भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह से मुकाबले में हार गए।पार्टी ने उनको टिकट न देकर अवधेश प्रसाद को इस बार उम्मीदवार बनाया है।पार्टी सेन परिवार के टिकट कटने की नाराजगी को कैसे दूर करेगी,ये देखना तो दूर की बात होगी। फिलहाल टिकट मिलने के बाद हनुमानगढ़ी में अवधेश ने टेका माथा।समाज वादी पार्टी से उम्मीदवार घोषित होने के बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व विधायक अवधेश प्रसाद सीधे बजरंग बली के दरबार में माथा टेकने हनुमानगढ़ी मंदिर अयोध्या पहुंचे।दर्शन करने के बाद उन्होंने कहा, पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाकर जो भरोसा जताया है।जन समर्थन से उस पर खरे उतरेंगे। बोले, जनता उनक चुनाव लड़ेगी।वह मोदी सरकार से छुटकारा चाहती है।

रवींद्र कुमार प्रवक्ता भूगोल बी के टी इण्टर कालेज लखनऊ राज्य अध्यापक पुरष्कार–2023 के लिए चयनित' किये गए

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शिक्षा विभाग से प्रत्येक वर्ष चयनित किये जाने वाले राज्य अध्यापक पुरष्कार की चयन सूची जारी कर दी गयी है जिसमें पूरे प्रदेश से कुल 11 (4 प्रधानाचार्य व 7 शिक्षकों) का चयन किया गया है। जे डी माध्यमिक कार्यालय लखनऊ के मण्डलीय विज्ञान प्रगति अधिकारी डॉ0दिनेश कुमार ने बताया कि चयन सूची में लखनऊ जनपद के बी के टी इण्टर कॉलेज के प्रवक्ता भूगोल रवींद्र कुमार का चयन किया गया है, डॉ0दिनेश कुमार ने बताया कि रवींद्र कुमार द्वारा समय समय पर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों से परिपूर्ण बी के टी इण्टर कॉलेज के छात्रों के लिए शिक्षण अधिगम के साथ साथ तमाम पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों को सम्पन्न करवाया जाता रहा है, डॉ0दिनेश कुमार ने बताया कि कुल 101 ऐडेड माध्यमिक विद्यालय हैं लखनऊ में। इस समय बी के टी इण्टर कॉलेज लखनऊ में कुल छात्र संख्या 4125 है जो लखनऊ जनपद के सभी ऐडेड माध्यमिक विद्यालयों में से किसी एक विद्यालय की सर्वाधिक छात्र संख्या है और रविन्द्र कुमार भूगोल विषय के प्रवक्ता हैं, भूगोल विषय पढ़ने वाले कुल छात्र संख्या लगभग 500 है, मतलब इण्टरमीडिएट में भूगोल पढ़ने वाले कुल छात्रों की संख्या 500 है जो अपने आप मे छात्रों द्वारा भूगोल विषय में रुचि लेने को दर्शाता है, किसी एक विषय मे इतनी छात्र संख्या होना उस विषय के अध्यापक की प्रवीणता को भी दर्शाता है जहां अन्य ऐडेड कई माध्यमिक विद्यालयों की कुल छात्र संख्या भी 500 नहीं है वही इनके कॉलेज में सिर्फ भूगोल विषय पढ़ने वाले छात्रों की संख्या ही 500 है वो भी सिर्फ इण्टरमीडिएट में। रवींद्र कुमार की सफलता के लिए विभागीय अधिकारियों ने उनको बधाई दी है, साथ ही उनको आगे आने वाले वर्षों में अपने बहुमुखी योगदान से छात्रहित में नए आयाम स्थापित करने के लिए प्रेरित भी किया।

पुलिस महानिदेशक, उद्प्रद्र की प्रशिक्षु आई.एफ.एस. अधिकारियों के साथ भेंटवार्ता

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। विजय कुमार, पुलिस महानिदेशक उ०प्र० से पुलिस मुख्यालय में 11 प्रशिक्षु आई.एफ.एस. (भारतीय विदेश सेवा) अधिकारियों द्वारा शिष्टाचार भेंट की गयी। उक्त प्रशिक्षु आई.एफ.एस. अधिकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुरूप पुलिस विभाग की कार्य प्रणाली से भिज्ञ होने हेतु पुलिस मुख्यालय में आगमन किये। पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० द्वारा भेंटवार्ता के दौरान प्रशिक्षु आई.एफ.एस. अधिकारियों को पुलिस कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए उनके जिज्ञासा भरे प्रश्नों का उत्तर दिया गया तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गयी। इस अवसर पर अपर पुलिस महानिदेशक /पुलिस महानिदेशक के जीएसओ, सहित पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण उपस्थित रहे।

नगर पंचायत खिरौनी में यूकेलिप्टस का पेड़ काटे जाने का मामला गरमाया

(डाक्टर अजय तिवारी
जिला संवाददाता)

अयोध्या। जिले के रौनाही थाना क्षेत्र के नगर पंचायत सुचित्तागंज खिरौनी के मजरे मोहन का पुरवा निवासी सुख राम पुत्र धनी राम खिरौनी गांव निवासी रंगी लाल पुत्र दुलीचंद सोहावल गांव निवासी पियूष रावत पुत्र स्व0 राम भवन पर नगर पंचायत ई ओ सचिन कुमार चौधरी ने मोहन का पुरवा के तालाब पर लगे यूकेलिप्टस के पेड़ काटने का आरोप लगाया है। रौनाही थाना प्रभारी को दिये गये शिकायती पत्र में उक्त तीनों आरोपियों द्वारा नगर पंचायत क्षेत्र में बिना विभागीय परमीशन के विवादित जमीन से हरे भरे पेड़ काटने पर मामले की जाँच के बाद दोषियों के विरुद्ध मुकदमा दर्जकर उचित कार्यवाही किए जाने की मांग की है।इस सम्बन्ध में पुलिस ने तहरीर मिलने और घटना की जांच कर कार्यवाही किये जाने की पुष्टि की है।

अयोध्या की गरिमा के अनुरुप श्रद्धालुओं को दें बेहतर सुविधाएं - डी.एम नितीश कुमार

–होटल व्यवसाइयों के साथ डीएम ने की बैठक।

(डीकेयू लाइव ब्यूरो) सुरेंद्र कुमार

अयोध्या जिलाधिकारी नितीश कुमार ने कलेक्ट्रेट सभागार में होटल व्यवसाइयों व धर्मशाला के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि अयोध्या एक धार्मिक एवं अध्यात्मिक पर्यटन नगरी के रूप में विश्व पटल पर प्रसिद्धि पा रही है और यह सांस्कृतिक राजधानी के रूप में उभरा है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के उपरांत अयोध्या धाम में श्रद्धालुओंध्पर्यटकों की आवक में तीव्र वृद्धि भी हुई है यहां आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को ठहरने एवं आवागमन की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करना सभी का कर्तव्य है। अतः यह सुनिश्चित किया जाये कि अयोध्या धाम आने वाले किसी भी पर्यटकध्श्रद्धालु से किसी भी होटल व्यवसाय द्वारा रेट बढ़ाकर न लिया जाये। उन्होंने सभी होटलों व धर्मशालाओं के मालिकों को अपने अपने होटलधर्मशाला का रेट लिस्टध्प्राइस बैण्ड को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने पर्यटकोंध्श्रद्वालुओं को होटलोंध्धर्मशालाओं में ठहरने हेतु रूम के दिये जाने वाली सुविधाओं यथा–वाहन, भोजन आदि अर्थात पैकेज में सम्मिलित समस्त सुविधाओं का स्पष्ट उल्लेख करने हेतु होटल/धर्मशालाओं के प्रतिनिधियोंध्मालिकों को निर्देशित किया। बैठक में सभी होटल व्यवसाइयों ने आश्वस्त किया कि प्राप्त निर्देशों का बेहतर ढंग से अनुपालन किया जायेगा और अयोध्या की गरिमा के अनुरूप आगुन्तकों से बेहतर से बेहतर सुविधाएं सुगमता से उपलब्ध करायी जायेगी। बैठक में अपर जिलाधिकारी नगर सलिल कुमार पटेल, सिटी मजिस्ट्रेट अरविन्द कुमार सहित विभिन्न होटलों एवं धर्मशालाओं के मालिक प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

साइबर हेल्प डेस्क ने वापस कराये 60 हजार रुपये

(डाक्टर अजय तिवारी
जिला संवाददाता)

अयोध्या।जिले के कैंट थाने के साइबर सहायता केंद्र ने ठगी के शिकार एक पीड़ित के बैंक खाते में 60 हजार से ज्यादा की रकम वापस कराई है।मंगलवार को सीओ सिटी शैलेन्द्र सिंह ने बताया कि एक जनवरी को एक शख्स ने खुद को सैन्य कर्मी बता प्लास्टर आफ पेरिस कराने का झांसा दिया था और ऑनलाइन भुगतान का वास्ता देकर पीड़ित के बैंक खाते से 60381.80 रूपये की धनराशि निकाल ली थी। पीड़ित ने यह पैसा अपने लड़के के इलाज के लिए एकत्र किया था। शिकायत पर मामला जाँच व कार्रवाई के लिए साइबर सहायता केंद्र को सौंपा गया था।केंद्र की ओर से ठगी गई रकम मंगलवार को वापस कराई गई है।

सुएज इंडिया ने सफाई मित्रों के लिए आयोजित किया ईएसआईसी स्वास्थ्य जांच शिविर

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। वन सिटी वन ऑपरेटर के तहत लखनऊ में सीवेज मैनेजमेंट के लिए उत्तरदायी सुएज इंडिया ने मंगलवार को लखनऊ में ईएसआईसी (कर्मचारी राज्य बीमा निगम) चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। यह आयोजन 345 एम.एल डी. एसटीपी, भरवारा, गोमती नगर में हुआ।

इस शिविर का उद्देश्य कामगारों को आवश्यक प्राथमिक स्वास्थ्य जांच सेवाएं प्रदान करना था, जो इस क्षेत्र के लोगों के कल्याण के लिए सुएज इंडिया की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। शिविर में कुल 112 सफाई मित्रों ने बीपी और शुगर परीक्षण सहित आवश्यक स्वास्थ्य जांच करवाई। जिन सफाई मित्रों के लिए आगे की जांच की आवश्यक थी, उन्हें निकटतम ईएसआईसी अस्पताल में रिपोर्ट करने के लिए डॉक्टरों ने मार्गदर्शन दिया, ताकि वे स्वास्थ्य सेवाओं का बेहतर लाभ उठा सकें। इस स्वास्थ्य जांच शिविर को सफल बनाने में विभिन्न पेशेवरों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मेडिकल टीम में डॉ विनय गुप्ता, डॉ अरुण वर्मा और डॉ अपर्णा सिद्धार्थ शामिल थे, जिन्होंने उपस्थित लोगों को चिकित्सा सहायता प्रदान की। श्री कमालदीप कुमार खैरवाल और श्री राहुल कुमार द्वारा नर्सिंग सेवाओं को कुशलता से संभाला गया। फार्मास्युटिकल पहलू श्री शारिक खान द्वारा प्रबंधित किया गया था, जिससे रोगियों के लिए आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित हुई। श्री सुजीत, श्री राहुल और श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा हाउसकीपिंग का काम पूरी दक्षता के साथ किया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ चंद्रिका प्रसाद पाल समन्वयक के रूप में उपस्थित थे, जिससे यह आयोजन निर्बाध रूप से आयोजित किया जा सका। डॉ. अरुण वर्मा ने ऐसे स्वास्थ्य शिविरों के महत्व पर जोर देते हुए कहा, ष्हेल्दी वर्कफोर्स के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच महत्वपूर्ण है, जिससे संभावित स्वास्थ्य समस्याओं का शीघ्र पता लगाया जा सके और समय रहते उचित इलाज हो सके। सुएज इंडिया के प्रोजेक्ट डायरेक्टर श्री राजेश मठपाल ने इस आयोजन पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, हमारा लक्ष्य समाज के स्वास्थ्य और खुशहाली में अपना योगदान देना है। ऐसे शिविर सामाजिक जिम्मेदारी और जनकल्याण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

जिला अस्पताल में संसाधनों की नीलामी में उचित बोली नही लगने चलते नीलामी हुई निरस्त – सीएमएस बृज कुमार

अयोध्या। जिला अस्पताल में संसाधनों की नीलामी में उचित बोली नही लगने के चलते नीलामी निरस्त कर दी गई।बताते चलें कि जिला अस्पताल में निष्प्रयोज्य सामान की नीलामी होनी थी।जिसकी आरक्षित दर 3.60 लाख रुपये रखी गई थी।जिला अस्पताल में मंगलवार को निष्प्रयोज्य सामान की नीलामी के लिए घंटों मशक्कत चली।इस दौरान अयोध्या के ही नहीं बल्कि लखनऊ, गोंडा और बलरामपुर से भी दर्जनों कबाड़ी सूट–बूट में नीलामी में शामिल होने पहुंचे थे। सामान की आरक्षित दर के सापेक्ष कबाड़ियों ने 2.5 लाख रुपये से अधिक की बोली नहीं लगाई।जिसके चलते नीलामी निरस्त कर दी गई।मालूम हो कि जिला अस्पताल में कुछ दिन पहले निष्प्रयोज्य सामान की नीलामी के लिए टेंडर प्रकाशित करवाए गए थे।दिसंबर में सामान की नीलामी होनी थी,लेकिन किसी कारण वश उक्त तिथि में परिवर्तन करते हुए 30 जनवरी को नीलामी तय की गई थी। इस दौरान कई जिलों से कबाड़ी सुबह 11 बजे ही जिला अस्पताल पहुंच गए।सुबह सबके काजजात जमा करा लिए गए।इसके बाद दो बजे रेडक्रॉस भवन में कमेटी बैठी,जिसमें अध्यक्ष जिला चिकित्सालय के सीएमएस डॉ.बृज कुमार,सदस्य के रूप में अधीक्षक डॉ. विपिन वर्मा,डॉ. अनिल वर्मा,मो. अकरम,राजेंद्र सिंह मौजूद थे। कबाड़ियों ने सामान देखा,इसके बाद कमेटी ने नीलामी की शुरू कराई। 51 हजार रुपये से बोली शुरू हुई। एक–एक करके कबाड़ियों ने बोली लगानी शुरू की।अंतिम बोली ढाई लाख रुपये की रही। आरक्षित दर तक किसी ने बोली नहीं लगाई।सामान नहीं दिखाना चाह रहा था। प्रशासन रेडक्रॉस भवन में नीलामी के लिए पहुंचे कबाड़ियों ने निष्प्रयोज्य सामान दिखाने की बात कही। इस दौरान जिला अस्पताल प्रशासन ने फाइल खोलकर सामान का ब्योरा देना शुरू कर दिया।इस पर कबाड़ी भड़क गए और उन्होंने पहले सामान दिखाने की बात कही।इस संबंध में जिला चिकित्सालय के अधीक्षक डॉ. विपिन वर्मा ने कबाड़ियों को सामान दिखाया।कबाड़ियों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि हमें सिर्फ जनरल ओटी का सामान दिखाया गया,जबकि ऑर्थो और फिजियोथैरेपी के सामानों का सिर्फ ब्योरा ही दिया गया था।उनका कहना था कि हल्के–हल्के सामान दिखाए गए थे।डीडी वापस कर दी गई अब फिर से निकालेंगे विज्ञापन जिला अस्पताल के सीएमएस डॉ.बृज कुमार ने बताया कि हमारी तरफ से 18 प्रतिशत जीएसटी को हटाकर कंडम सामान की आरक्षित दर 3.4 लाख रुपये रखी गई थी।कोई भी इससे एक हजार रुपये आगे नहीं बोल पाया।इसलिए अभी के लिए नीलामी निरस्त कर दी है। मैं बुधवार को प्रशासिनक कार्यों को छोड़कर मरीजों की सेवा में जुट जाऊंगा।उसके बाद जो भी सीएमएस आएंगे वह फिर से विज्ञापन निकलवाकर नीलामी करवाएंगे।

योगी के गोरक्षपीठ द्वारा राममंदिर हेतु संघर्षो को बताती शशि प्रकाश की डाक्यूमेंट्री

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। अयोध्या के भव्य श्री राम मंदिर हेतु नाथ पंथ के अति प्राचीन मठ गोरक्ष पीठ के संघर्षो को बताने वाली शिक्षाविद् शशि प्रकाश सिंह की डॉक्यूमेंट्री लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह से भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से भी दो वर्ष पहले 1855 में ही गोरक्ष पीठ ने राम मंदिर के लिए संघर्ष प्रारंभ कर दिया गया था जो वर्तमान पीठाधीश्वर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में जाकर पूर्ण हुआ है।

डॉक्यूमेंट्री में बताया गया है की किस तरह से योगी आदित्यनाथ के दादा गुरु महंत दिग्विजय नाथ ने 1949 में रामलला की मूर्तियों के प्रकटीकरण के दौरान राम मंदिर निर्माण की पृष्ठभूमि तैयार की उसके बाद उनके शिष्य और योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैद्यनाथ ने मामले को आगे बढ़ाया और योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में उसका परिणाम आ रहा है। डाक्यूमेंट्री के निर्माता ब्लॉसम इंडिया फाउंडेशन के निदेशक और राष्ट्रीय व अंतराष्ट्रीय स्तर के कई पुरस्कार प्राप्त कर चुके प्रख्यात शिक्षाविद् शशि प्रकाश सिंह ने बताया कि डॉक्यूमेंट्री के सिलसिले में उन्होंने कई किताबों का अध्ययन किया व नाथ पंथ के विशेषज्ञों, मंदिर प्रबंधन से जुड़े लोगों व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ काम कर रहे कई अधिकारियों समेत विभिन्न लोगों से उन्होंने बातचीत किया और एक शोधपरक व प्रामाणिक डॉक्यूमेंट्री का निर्माण किया है। शशि प्रकाश की डॉक्यूमेंट्री में बताया गया है की किस तरह से 1949 में अयोध्या के तत्कालीन जिला अधिकारी के के नायर लाल टेनिस खेलने के शौकीन थे,वे दिग्विजय नाथ से प्रभावित थे। किस तरह से महंत अवैद्यनाथ नाथ द्वारा 1986 में ताला खुलवाने के लिए वीर बहादुर सिंह के साथ उनकी बैठक हुई थी। इसके अलावा दलित जाति के

कामेश्वर चौपाल से शिलान्यास महंत अवैद्यनाथ के कहने पर ही करवाया गया था डॉक्यूमेंट्री में बताया गया है की योगी आदित्यनाथ की गोरक्षपीठ ऊंच नीच,जाति पांति व भेदभाव को नहीं मानती है व सबको साथ लेकर चलने वाली पीठ रही है। अंतरराष्ट्रीय स्तर की पत्रिका फोर्ब्स की सुर्खियां बन चुके शशि प्रकाश सिंह ने कोरोना काल में 2100 छात्रों की आर्थिक मदद की थी, शशि प्रकाश सिंह को पद्मश्री के लिए नामांकित करने हेतु कई सांसदों ने गृहमंत्री व प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था।

प्रशान्त कुमार, पुलिस महानिदेशक कानून–व्यवस्था को उत्तर प्रदेश पुलिस के डी०जी०पी० का सौंपा गया कार्यभार

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। आज दिनांकः 31.01.2024 को श्री प्रशान्त कुमार द्वारा पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० का पदभार ग्रहण किया गया। वर्ष 1861 में व्यवस्थापित पुलिस की गौरवशाली परम्परा में वर्ष 1952 में पुलिस कलर प्राप्त हुआ तथा विश्व के विशालतम पुलिस बल का नेतृत्व आई०जी०पी०डी०जी०पी० रैंक के अधिकारियों द्वारा किया गया। उसी गौरवशाली परम्परा के ध्वज वाहक के रूप में श्री प्रशान्त कुमार आई०पी०एस०, डी०जी०पी० यू०पी० बनाये गये हैं। श्री प्रशान्त कुमार वर्ष 1990 बैंच के आई०पी०एस० अधिकारी हैं, जो मूलरूप से सीवान (बिहार) के रहने वाले है। श्री प्रशान्त कुमार की शिक्षा–दीक्षा बिहार व दिल्ली विश्वविधालय में पूर्ण हुई। एप्लाईड जियोलॉजी विषय में एम०एस०सी० गोल्ड मेडलिस्ट होने के साथ ही साथ डिफेंस एण्ड स्ट्रेटजिक स्टडीज में एम० फिल० करने के उपरान्त डिजास्टर मैनेजमेन्ट में एम०बी०ए० की डिग्री भी प्राप्त की। श्री प्रशान्त कुमार को उ०प्र० पुलिस में सेवा करने का एक लम्बा अनुभव है। उ०प्र० के बरेली व वाराणसी जनपदों से एएसपी के रूप में कार्यकाल शुरू करते हुये भदोही, सोनभद्र, जौनपुर, फैजाबाद, बाराबंकी, सहारनपुर जनपदों में पुलिस अधीक्षक ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व सहारनपुर, फैजाबाद, मिर्जापुर, मेरठ जैसे मण्डलों में डीआईजी रेंज के पद पर कार्यरत रहे। पदोन्नत के उपरान्त आईजी के रूप में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर सीआईएसएफ व आईटीबीपी जैसे केन्द्रीय बलों में सेवा प्रदान किये। वर्ष 2015 में एडीजी के पद पर पदोन्नत होने के उपरान्त एडीजी पीएसी, एडीजी सुरक्षा, एडीजी यातायात उ०प्र० के पद पर सफलता पूर्वक कार्य करते हुये वर्ष 2017 में एडीजी मेरठ जोन के पद पर नियुक्त हुये। एडीजी मेरठ के पद पर रहते हुये कानून–व्यवस्था व अपराध नियन्त्रण के विभिन्न अवसरों पर सराहनीय योगदान दिये और यहीं से संगठित अपराध के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की रणनीति तैयार कर पश्चिमी उ०प्र० को अपराध मुक्त किये। सीएए, एनआरसी व श्रीराम जन्मभूमि निर्णय के दौरान कानून–व्यवस्था व शान्ति व्यवस्था को सुनिश्चित किये। वर्ष 2020 में उ0प्र0 के एडीजी कानून व्यवस्था के पद पर नियुक्त होने के उपरान्त पूरे प्रदेश में सरकार की प्राथमिकताओं के अनुसार अपराध नियन्त्रण, कानून–व्यवस्था, शान्ति–व्यवस्था सुनिश्चित करने में उ०प्र० पुलिस को कुशल नेतृत्व प्रदान करते हुये कई कीर्तिमान स्थापित किये हैं। भारत सरकार की तरफ से कैलाश मानसरोवर यात्रा में भारत व चीन राष्ट्र के मध्य मुख्य समन्वयक के रूप में कार्य करते हुये हजारों तीर्थ यात्रियों की यात्रा को सुगम बनाये। श्री प्रशान्त कुमार को वीरतापूर्ण कार्यों के लिये 04 बार गैलेन्ट्री मेडल से

सम्मानित किये जाने के साथ–साथ सराहनीय सेवाओं के लिये राष्ट्रपति का पुलिसपदक, दीर्घकालीन सेवाओं के लिये राष्ट्रपति का पुलिस पदक, उत्कृष्ट सेवाओं के लिये मा० मुख्यमंत्री जी का उत्कृष्ट सेवा पुलिस पदक, मा० मुख्यमंत्री जी कुम्भ मेला पदक, पराकम पदक, मा० गृहमंत्री जी, भारत सरकार का उत्कृष्ट सेवा पदक, डीजी सी०आई०एस०एफ० कमंडेशन डिस्क, डीजी आई०टी०बी०पी० कमंडेशन डिस्क सिल्वर, डीजी आई० टी० बी०पी० कमंडेशन डिस्क गोल्ड, डीजी यू०पी० कमंडेशन डिस्क सिल्वर, डीजी यू०पी० कमंडेशन डिस्क गोल्ड, डीजी यू०पी० कमंडेशन डिस्क प्लेटिनम से सम्मानित किया गया है।

हिन्दी सांध्य दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित ।

सम्पादक
श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0–7007415808,9628325542,9415034002

RNI संन्दर्भ संख्या – 24/234/2019/R-1

deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से सम्बन्धित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायलय होगा।